सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 181, नई दिल्ली । मंगलवार, 10 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 वीके सक्सेना दिल्ली के सबसे अक्षम एलजी, उनसे नहीं संभल रही कानून-व्यवस्था...

06 स्वास्थ्य सेवा में बदलाव के लिए शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता

08 मालकानगिरि में भारी बारिश ।बारिश का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग...

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग किसके लिए, आम जनता या फिर उद्योगपतियों के लिए, करे फैसला

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली का ऐसा विभाग जहा पर दिल्ली के सभी घरों के किसी ना किसी सदस्य या सभी सदस्यों को कार्य अवश्य पड़ता है, यानी वह विभाग जिसके बिना किसी का गुजारा नहीं। दिल्ली परिवहन विभाग आज पिछले 5 सालों से दिल्ली की जनता के लिए नही अपितु दिल्ली में राजस्व हित के साथ उद्योगपतियों के हित में काम कर रहा है। यह बात हम बिना कारण नही बोल रहे। इसके लिए आप भी चाहे तो इन 5 वर्षो में परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा किए गए आदेशों निर्देशों को आरटीआई में मांग कर जांच कर सकते हैं।

आपकी जानकारी हेतु बता दें पर यह सभी आदेश निर्देश जनहित के नाम से किए गए हैं

1. इन 5 वर्षो मे परिवहन विभाग द्वारा जनता के लिए नोटिफिकेशन कर जनहित में खोले हुए 5 क्षेत्रीय कार्यालयो को बिना पूर्व सूचना के जनहित में बंद कर सरकार के सैलरी में जानें वाले लाखों रुपए बचाए,

2. दिल्ली के सभी क्षेत्रीय कार्यालयो मे जनता के हित में छपने वाली आरसी, लाइसेंस, बेज और कंडक्टर लाइसेंस जनहित में बंद करवाकर एक कम्पनी को एक ही जगह छापने का ठेका (टेंडर) प्रदान कर दिया, एनओसी लेकर वाहन को दूसरे राज्य में बेचने पर जिस आरसी की हाथो हाथ जरूरत होती है वह विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा बेचने वाले के घर ना की वाहन खरीदने वाले के घर भिजवाने के आदेश जारी कर जनहित का कार्य किया,

3. दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों की जांच जो बुराड़ी और झुलझूली के दो सेंटर पर होती थी उसे सिर्फ़ झुलझूली वाहन जांच केंद्र पर भेजने के आदेश जारी कर दिए जिससे दिल्ली के तमाम व्यवसायिक वाहन दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पर भटकते और परेशान होकर अपना रोजगार बदल ले,

4. दिल्ली को पिछले 11 साल में

जनता को सुखद सुरक्षित सार्वजनिक सवारी सेवा के लिए एक भी बस दिल्ली सरकार के राजस्व से खरीद कर उपलब्ध नहीं करवाई उल्टा समय सीमा तय कर चुकी बसों को ही 5 साल और स्टेज कैरिज रूट पर चलाने के आदेश देकर जनता को सड़को पर कई भी खड़ी हो जानें वाली या जल जानें वाली बसों में जनहित में यात्रा के लिए मजबूर कर दिया,

5. दिल्ली की जनता को सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने की जगह प्रीमियम प्राइवेट उद्योगपतियों की बसों को चलने की इजाजत दे दी वह भी इस शर्त के साथ की कोई भी डीटीसी से कम किराया सवारी से चार्ज नहीं करे अन्यथा भारी जुर्माना लगाया जायेगा पर अधिक कितना भी ले विभाग और सरकार को कोई एतराज नहीं,

6. डीटीसी जो जनता को भरोसेमंद सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने का सरकारी निकाय है की सभी बसे समाप्त करवा कर बड़े उद्योगपतियों के द्वारा दिल्ली में बसे चलवा रहे हैं,

7. ओला, उबर जैसी कंपनियों पर बंदिश लगाने की जगह उन के द्वारा प्राईवेट नंबर में पंजीकृत वाहनों से भी व्यवसायिक गतिविधियों पर भी कार्यवाही नहीं कर जनता को सुरक्षित बिना नियम की सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं,

8. दिल्ली में जनता के लिए नियम एक व्यक्ति के नाम एक आटो पर बड़ी कंपनियों को एक ही नाम से 100 से भी अधिक परमिट जारी कर रहे हैं,

9. आम जनता के लिए एक नाम से मात्र एक ई रिक्शा पंजीकरण पर बड़े दबाव वाले व्यक्तियों के नाम अनगिनत ई रिक्शा पंजीकरण कर रहे हैं,

10. जनता के घरों में खड़े वाहनों से भी प्रदूषण हो रहा है कहकर उन्हें अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत बड़े उद्योगपतियों वाहन स्क्रैप डीलरो को उठा कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में सैकडो बड़े फले फूले हरे भरे पेड़ों को कटवा कर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना रहे हैं,

11. दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पालिसी को आगे बढ़ाने की जगह जनता पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी रोड टैक्स पंजीकरण फीस शुरू करवा कर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना रहे हैं,

एक अमीर आदमी दिल्ली मे कई घर खरीद सकता है, कई ट्रक खरीद सकता है लेकिन एक गरीब आटो वाला सिर्फ एक ही आटो खरीद सकता है, अगर मेहनत करके उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर भी लिए तब भी दिल्ली सरकार का कानून उसे दूसरा आटो खरीदने की अनुमति नहीं देता पर एक उद्योगपति को 100 से अधिक परमिट देने की इजाजत देता है। **वाह रे दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी का कानून जो** अमीर को तो **अमीर बनाने मे मदद करता है लेकिन गरीब को और गरीब बनाना चाहता है।**

एनएच-9 पर लगा लंबा जाम, 7 दिनों तक बंद रहेगा पांडव नगर फ्लाईओवर, उपयोग करें ये रूट

पांडव नगर फ्लाईओवर अगले 7 दिनों तक बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने रविवार शाम को बताया कि मरम्मत का काम चलने की वजह से इस फ्लाईओवर को एक सप्ताह के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। जानिए दिल्ली पुलिस ने फ्लाईओवर के बजाय कौन सा रूट बताया है?

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पांडव नगर फ्लाईओवर से चलने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पांडव नगर फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य चलने से एनएच-9 व एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा है। यह परेशानी एक सप्ताह तक परेशानी झेलनी पड़ेगी।

दरअसल, Delhi Traffic Police ने रविवार शाम को बताया कि मरम्मत का काम चलने की वजह से फ्लाईओवर को 7 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सात दिनों तक इस रूट पर आने बचें।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (एनएच-9) पर गाजीपुर से सराय काले खां तक के कैरिजवे पर पांडव नगर फ्लाईओवर पर डेक स्लैब पर सुधार कार्य रविवार को शुरू हुआ है। यह कार्य सात दिनों तक किया जाएगा।

वहीं, कहा गया कि इसके कारण, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (एनएच-9) पर पांडव नगर फ्लाईओवर की बाईं लेन इस अवधि के दौरान प्रभावित रहेगी।

ट्रैफिक पुलिस ने दी ये सलाह

यातायात पुलिस ने कहा कि एनएच-9 के माध्यम से गाजीपुर की ओर से सराय काले खां की ओर जाने वाले यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए इस अवधि के दौरान अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एनएच-9 के बजाय एनएच-24 का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

दिल्ली पुलिस ने मेट्रो में पाई कई खामियां, डीएमआरसी से हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा

दिल्ली मेट्रो में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर मेट्रो पुलिस ने सुरक्षा ऑडिट कराया है। ऑडिट में कई खामियां पाई गई हैं जिनमें सीसीटीवी कवरेज की कमी ब्लैक स्पॉट प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की कमी और पेड़ों की कटाई-छंटाई का अभाव शामिल है। मेट्रो पुलिस ने डीएमआरसी को पत्र लिखकर इन खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राजधानी में आबादी बढ़ने के साथ-साथ दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) मेट्रो स्टेशनों का विस्तार तो करती जा रही है, लेकिन मेट्रो परिसरों में सुरक्षा के बाबत अधिक ध्यान नहीं दे रही है, जिससे मेट्रो परिसरों में यात्रियों के साथ दिन प्रतिदिन आपराधिक वारदातें बढ़ने लगी हैं। अपराध बढ़ने के कारणों का पता लगाने के लिए मेट्रो पुलिस द्वारा हाल में कराए गए सुरक्षा ऑडिट में विभिन्न तरह की खामियां पाई गई।

मेट्रो पुलिस के विशेष आयुक्त रोबिन हिब्बू ने इसे दूर करने के लिए डीएमआरसी को पत्र लिख मेट्रो परिसरों के बाहर की तरफ भी जल्द से जल्द हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने के अलावा, निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती और अंधेरे वाले जगहों पर पर्याप्त लाइटें लगाने का अनुरोध किया गया है।

परिसर के बाहर लाइट नहीं रहने से बढ़ रहे अपराध

पत्र में कहा गया है कि कई मेट्रो स्टेशन परिसर में बाहर की तरफ बिजली की व्यवस्था न होने के कारण रात के समय अंधेरा पसरा रहता है, जिस कारण अपराधी, यात्रियों के साथ लूटपाट, झपटमारी, चोरी व महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि पहले भी कई बार मेट्रो पुलिस की ओर से इस तरह का सुझाव दिया गया है लेकिन सुरक्षा के मसले पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

खालिस्तानी नारे लिखे जाने से खामियां उजागर

हाल के वर्षों में मेट्रो की दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे जाने के मामले ने डीएमआरसी के सुरक्षा ढांचे में खामियों को उजागर किया है। सुरक्षा आडिट में कई गंभीर कमियों की पहचान की गई हैं। सीसीटीवी कवरेज अपर्याप्त हैं, मेट्रो ट्रैकों पर कई जगहों पर ब्लैक स्पाट यानी वहां अंधेरा पसरा रहता है। ऐसे में परिसर के चारों तरफ, पार्किंग में व साइड ट्रैक सहित चिह्नित किए गए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है।

हर मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाने की मांग

मेट्रो स्टेशनों पर रेल के सामने छलांग लगा यात्री खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ ही मेट्रो स्टेशनों पर प्लेटफार्म स्क्रीन डोर लगे हुए हैं। इसके लगे होने से यात्री रेल के सामने छलांग नहीं लगा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हर मेट्रो स्टेशन पर करने के लिए फिर से कहा गया है। यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्लेटफार्म स्क्रीन डोर लगाना बहुत अनिवार्य है।

पेड़ों की कटाई-छंटाई पर भी ध्यान देने की अपील

मेट्रो परिसरों और ट्रैकों के किनारे लगे पेड़ों की कटाई छंटाई पर भी ध्यान देने को कहा गया है। परिसर की सुरक्षा के लिए दीवारों पर कंटीले तार व लोहे की ग्रिल लगाने व मरम्मत के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। मेट्रो ट्रैकों व यार्ड पर विशेष रूप से रात के समय अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात करने को कहा गया।

दिल्ली-एनसीआर में कुल 288 मेट्रो स्टेशन हैं, जिनमें 256 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में हैं। इनमें 192 स्टेशन अधिसूचित हो चुके हैं। जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेट्रो पुलिस के जिम्मे है। अन्य मेट्रो स्टेशन जो अधिसूचित नहीं हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय थाना पुलिस के जिम्मे हैं। दिल्ली में कुल 16 मेट्रो थाने हैं, आरआरटीएस मेट्रो के पांच नए थाने और बनने हैं।

दिल्ली तक कब दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन? अब नहीं करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार; इसी साल शुरू होगा ट्रायल

परिवहन विशेष न्यूज

नमो भारत ट्रेन के दिल्ली तक चलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। नमो भारत ट्रेन के दिल्ली तक चलने पर सबसे ज्यादा फायदा नोएडा में नौकरी करने वालों को होगा। क्योंकि न्यू अशोक नगर स्टेशन नोएडा के बहुत पास में है। वहीं NCRTC की ओर से नवंबर माह में न्यू अशोक नगर तक ट्रायल होने की बात कही गई है।

नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन के दिल्ली तक चलने का इंतजार कर रहे लोगों को लिए एक खुशखबरी है। वैसे तो मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक नमो भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है, लेकिन अभी नोएडा में जॉब करने वालों को इसका बेसब्री से इंतजार है।

दिल्ली तक चलने में अभी कितना करना होगा इंतजार

मेरठ से दिल्ली तक नमो भारत से सफर करने के लिए अभी कम से कम दो-तीन महीने का इंतजार करना होगा। हालांकि, एनसीआरटीसी ने ट्रायल को लेकर घोषणा कर दी है। उम्मीद है कि सफल ट्रायल होने के बाद लोग नमो भारत ट्रेन से दिल्ली तक सफर कर सकेंगे। न्यू अशोक नगर तक इस साल भी ट्रेन

का संचालन हो सकता है।

अब न्यू अशोक नगर तक ट्रायल होने में सिर्फ दो महीने

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी NCRTC) ने हाल ही में बताया कि इसी साल नवंबर महीने में साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर New Ashok Nagar Station के बीच करीब 12 किलोमीटर के खंड पर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। खास बात है कि साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के बीच काम बहुत तेजी से चल रहा है। न्यू अशोक नगर का स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ फिनिशिंग का कार्य बचा है।

महज 40 मिनट में तय होगा सफर

साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक ट्रायल होने के बाद नमो भारत ट्रेन Namo Bharat Train का संचालन शुरू हो जाएगा। फिर मेरठ साउथ से लेकर न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन फर्राटा भरेगी। वहीं, न्यू अशोक नगर तक चलने पर सबसे ज्यादा नोएडा में नौकरी करने वालों को इसका फायदा होगा। वे मेरठ से मात्र 40 मिनट में नोएडा पहुंच जाया करेंगे। ऐसे में उनके समय की बहुत बचत होगी।

कितना हो सकता है मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर का किराया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के अनुसार, अभी मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक स्डैंडर्ड कोच का किराया 110 रुपये है, Namo Bharat Ticket जबकि प्रीमियम कोच का किराया 220 रुपये है। अभी मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर का किराया निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन मेरठ साउथ से न्यू अशोक तक स्डैंडर्ड क्लास का किराया 150 रुपये के आसपास रखा जा सकता है। हालांकि, इससे कम भी हो सकता है।

लगभग पूरा हो चुका न्यू अशोक नगर स्टेशन का काम

न्यू अशोक नगर स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। कॉनकोर्स और प्लेटफॉर्म लेवल पूरे हो चुके हैं और छत का काम प्रगति पर है। न्यू अशोक नगर तक ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। ओएचई और सिग्नलिंग का काम भी प्रगति पर है। बताया गया कि न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन की लंबाई लगभग 215 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

ऐसे हुई थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना, यहां एक साथ की जाती है शिव-पार्वती की पूजा

शालिनी बाजपेयी

मल्लिकार्जुन शब्द में मल्लिका का अर्थ है मां पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव से हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस ज्योतिर्लिंग के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मां पार्वती और भगवान शिव का है।

जब भी हम किसी शिव मंदिर में दर्शन व पूजन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ भगवान शिव विराजमान होते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि देशभर में 12 ज्योतिर्लिंग है। हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी और मान्यता है। लेकिन आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां शिवलिंग पर भगवान शिव के साथ मां पार्वती की भी पूजा की जाती है।

दरअसल, इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है।

बता दें कि मल्लिकार्जुन शब्द में मल्लिका का अर्थ है मां पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव से हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस ज्योतिर्लिंग के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मां पार्वती और भगवान शिव का है। ऐसे में हम आपको इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक बातों के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी।

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग

भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित प्राचीन और फेमस तीर्थस्थल है। भगवान गणेश और कार्तिकेय स्वामी की इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक रोचक कथा है।

प्राचीन कहानी

भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश हैं। जब कार्तिकेय और गणेश जी विवाह के योग्य हुए। तो मां पार्वती और भगवान शिव ने दोनों की शादी कराने की सोची। ऐसे में भगवान शंकर ने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और उनके विवाह के बारे में बताते हुए शर्त बताई। भगवान शिव ने दोनों को शर्त बताते हुए कहा कि जो भी इस संसार की पहले परिक्रमा करके वापस आएगा, वह पहले उस पुत्र की शादी कराएंगे। यह सुनकर कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर संसार की परिक्रमा लगाने चले गए।

वहीं भगवान गणेश का वाहन मूषक था, ऐसे में वह सोचने लगे कि वह कार्तिकेय से पहले संसार की परिक्रमा कैसे कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने माता-पिता यानी की भगवान शिव और मां पार्वती की परिक्रमा कर ली। भगवान गणेश ने कहा कि उनके लिए तो शिव-पार्वती ही पूरा संसार हैं। गणेश की बात सुनकर भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी का पहले विवाह करा दिया। वहीं जब कार्तिकेय जी वापस आए, तो उन्होंने देखा कि श्रीगणेश का विवाह संपन्न हो चुका है।

जब सारी बात कार्तिकेय को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध में कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। यह पर्वत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। वहीं इस पर्वत को श्रीशैल और श्रीपर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती ने कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानें। जब शिव पार्वती को लगा कि अब कार्तिकेय वापस कैलाश नहीं आएंगे, तो उन्होंने तय किया कि वह अपने पुत्र से मिलने समय-समय पर वहां जाएंगे।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती रूप बदलकर कार्तिकेय स्वामी को देखने पहुंचते थे। जब कार्तिकेय स्वामी को यह पता चला, तो उन्होंने वहां पर एक शिवलिंग स्थापित किया और इसी शिवलिंग में भगवान शिव और मां पार्वती ज्योति रूप में विराजमान हो गए। मान्यता है कि आज भी हर अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णिमा पर मां पार्वती कार्तिकेय स्वामी से मिलने श्रीपर्वत पर पहुंचते हैं।

शादी से पहले पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं हसीन पल, तो इन सस्ती जगहों पर जाएं घूमने

शादी से पहले ही यदि आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ लेते हैं और उनके साथ बढ़िया तालमेल बैठ जाता है। ऐसे में पार्टनर को समझने और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आप कुछ रोमांटिक जगहों पर जा सकते हैं।

शादी से पहले ही यदि आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ लेते हैं और उनके साथ बढ़िया तालमेल बैठ जाता है। तो बाकी की जिंदगी खुशी-खुशी गुजरती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बीच लड़ाई-झगड़े नहीं होंगे। लेकिन जरूरी यह होता है कि आप अपने रिश्ते को किस तरह से संभालते हैं।

ऐसे में अगर आप भी शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको भारत की कुछ रोमांटिक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

नैनीताल

अगर आप कम बजट में पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको नैनीताल से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। यह उत्तराखंड की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। नैनीताल कपल्स का रोमांटिक डेस्टिनेशन है। यह जगह समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर है। आप यहां पर अपनी आंखों के सामने बादलों को बनते देख सकते हैं। यहां का नजारा आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पार्टनर के साथ नए रिश्ते की शुरूआत करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है।

कर्नाटक का चिकमंगलूर

कर्नाटक का चिकमंगलूर एक ऐसा हिल स्टेशन है, जो बारिश के मौसम में स्वर्ग की तरह लगता है। बता दें कि कम बजट वाले लोगों के लिए यह बेहद शानदार जगह है। आपको यहां पर कपल्स नजर आएंगे। क्योंकि यह भारत के रोमांटिक डेस्टिनेशन में से एक है। यहां पर चाय-कॉफी के बागानों के अलावा खूबसूरत झरने आपके ट्रिप को ज्यादा यादगार बनाने का काम करेंगे।

मुन्नार

शादी के पहले पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने के लिए आप मुन्नार जा सकते हैं। यह भारत में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहां आप अच्छे तीर्थ स्थानों के साथ हरे-भरे चाय के बागानों और कॉफी के बागान देखने को मिलेंगे। आप यहां पर भगवान के आशीर्वाद लेने के साथ एक-दूसरे को समझने के लिए अच्छा समय बिता सकते हैं।

ऊटी

अगर आप शादी से पहले पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नीलगिरि पहाड़ों में बसे ऊटी का नजारा देखने जा सकते हैं। शादी के बाद भले ही आप अपने पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बनाएंगे, लेकिन आप यह ट्रिप पार्टनर के साथ नहीं भूल पाएंगे। ऐसे में शादी से पहले पार्टनर के साथ बिताए गए पल हर कपल्स के लिए बेहद खास होते हैं। वहीं यदि आप भी अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप पार्टनर के साथ ऊटी का ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक के लिए एक्ट्रेसेस के लुक से लें आइडिया, लगेंगी रूप की रानी

महिलाएं शादी या अन्य किसी फंक्शन में परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए लहंगा वियर करना पसंद करती हैं। ऐसे में आप भी एक्ट्रेसेस के लुक्स से आइडिया लेकर लहंगा को शादी के अलावा अन्य कई फंक्शन में कैरी कर सकती हैं।

महिलाएं शादी या अन्य किसी फंक्शन में परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए लहंगा वियर करना पसंद करती हैं। लहंगे में महिलाएं बेहद खूबसूरत लगती हैं और लुक भी सबसे अलग होता है। वहीं आप भी यदि शादी में पहनने के लिए एक्ट्रेसेस की तरह परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो हम आपको कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियों के लहंगा लुक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी इनके लुक्स से आइडिया लेकर शादी के अलावा अन्य कई फंक्शन में कैरी कर सकती हैं।

गोल्डन लहंगा

परफेक्ट ट्रेडशिनल लुक के लिए गोल्डन लहंगा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस तरह के लहंगे में एम्ब्रायडरी की गई है। आप हल्दी या फिर रिसेप्शन के दौरान इस लहंगे को वियर कर सकती हैं। वहीं आप एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के लुक से इस लहंगे को स्टाइल करने का आइडिया ले सकती हैं। आप इसके साथ झुमके या चोकर स्टाइल वाली ज्वेलरी कैरी कर सकती हैं। आप मार्केट या फिर किसी डिजाइनर से सिलवा सकती हैं। मार्केट में आपको यह लहंगा 3000 रुपए तक में आसानी से मिल जाएगा।

पेस्टल लहंगा

इस तरह के लहंगे को आप शादी जैसे फंक्शन में कैरी कर सकती हैं। आप इस आउटफिट के साथ कुंदन वर्क वाली ज्वेलरी और हील्स वाली फुटवियर पहन सकती हैं। बता दें कि इस तरह के लहंगे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में 5,000 रुपए तक में आसानी से मिल जाएंगे। वहीं आप चाहें तो इस तरह के लहंगे को डिजाइन भी करवा सकती हैं।

फिश टेल स्कर्ट

अगर आप भीड़ में अगल नजर आना चाहती हैं, तो आप फिश टेल स्कर्ट भी वियर कर सकती हैं। बता दें कि इस तरह के आउटफिट के साथ आप कुंदन वर्क वाली ज्वेलरी के साथ झुमके स्टाइल कर सकती हैं। मार्केट में इस तरह के लहंगे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में 3000 से 5000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे।

लहसुन के तेल के फायदे जानकर हैरान हो जाएंगे आप, घर पर कैसे बनाएं गार्लिक ऑयल

खाने के स्वाद में जान डालने वाला लहसुन के फायदे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लहसुन सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को भी दूर कर सकता है। लहसुन के तेल हेयर फॉल से लेकर फंगल इंफेक्शन को दूर करता है। आइए जानते हैं इसके फायदे।

हर घर में लहसुन खाने में जरुर डाला जाता है। भोजन में लहसुन का इस्तेमाल करके स्वाद बढ़ाया जाता है। कई लोगों को नहीं पता होगा लहसुन स्वाद के साथ ही हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। आज हम आपको लहसुन के तेल के फायदे बताने जा रहे हैं, इसे घर में बनाना काफी आसान है। आइए जानते हैं लहसुन के तेल के फायदे और उसको बनाने का तरीका।

लहसुन के तेल में पाए जाने वाले पोषक तत्व

लहसुन के ऑयल में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी मौजूद होता है। गार्लिक तेल सेहत को कई फायदे पहुंचा सकता है।

फंगल इंफेक्शन दूर होना

गार्लिक ऑयल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। इससे त्वचा हेल्दी बनी रहती है और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याओं से बचाव हो जाता है।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल

लहसुन के तेल हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण असंतुलित ब्लड प्रेशर माना जाता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण हृदय रोग का जोखिम बढ़ता है। ऐसे में लहसुन का तेल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। हालांकि, इसके सेवन से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरुर लें।

हेयर फॉल

बदलते मौसम में हेयर फॉल की समस्या काफी बढ़ जाती है। अगर आपके बाल भी इस मौसम में बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, लहसुन का तेल हेयर फॉल को रोकता है। इस उपाय को करने के लिए स्कैल्प पर लहसुन के तेल से मालिश करें।

दांतों के दर्द से छुटकारा

लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाएं जाते हैं जो दांत का दर्द दूर करता है। लहसुन के तेल का इस्तेमाल करके दर्द को आसानी से कम कर सकते हैं। इससे दांत स्वस्थ बने रहते है और दर्द भी दूर हो जाता है।

एक्ने की समस्या

लहसुन मे विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक और कॉपर जैसे गुण के अलावा एंटी-इंफ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण भी मौजूद होते हैं, यह एक्ने की समास्या से निजात दिलाता है। गार्लिक ऑयल की एक बूंद भी आपके चेहरे के पिंपल्स को दबा सकती है।

घर पर कैसे बनाएं लहसुन का तेल

सबसे पहले आप लहसुन की कुछ कलियां लेकर उन्हें कुचल लें। फिर आप थोड़े से जैतून के तेल के साथ पैन में डालकर भून लें। फिर इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए गर्म करके एक एयर-टाइट कांच के कंटेनर में भरकर अलग किसी नमी वाली जगह पर रख दें।

गोपाल राय अपनी नाकामियों से बचने के लिए विंटर एक्शन प्लान को नया अमली जामा पहनाकर पेश कर रहे है।- देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित न कर पाने का डर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को सताने लगा है इसलिए अगस्त माह के अंतिम दिनों में प्रदूषण नियंत्रण के 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद उसमें संशोधन करके उसे 21 दिन का विंटर एक्शन प्लान बनाकर घोषणा करना दिल्ली वालों को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि सभी संसाधन, सत्ता, अधिकारी और कर्मचारी होने के बावजूद गोपाल राय प्रदूषण को नियंत्रित करने में आश्वस्त अथवा सुनिश्चित नहीं है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षो से दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, सरकार साल दर साल अपने आपको असहाय घोषित करके प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों व अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराती आ रही है। केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता वायु प्रदूषण से प्रत्येक दिल्लीवासी के जीवन के सात वर्ष कम हो रहे है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब गोपाल राय प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिले 742.69 करोड़ में से सिर्फ 29 प्रतिशत ही खर्च कर पाए, फिर अब क्यों मंत्री महोदय कैसे प्रदूषण नियंत्रण करने का दावा कर रहे

है, इसका जवाब दें?

उन्होंने कहा कि जब हर वर्ष दिल्ली सरकार सर्दियों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाती रही है, तब इसे भी विंटर एक्शन प्लान में पहले ही शामिल किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पिछली बातों को दोहराकर लोगों से झूठी सहानुभूति लेने के लिए हर विषय को इंवेंट बनाकर पेश करने की नीति बना ली है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगना चाहिए परंतु यह प्रतिबंध केवल घोषणा के लिए नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा तो गोपाल राय ने की है परंतु क्या वे इस पर अमल करवा पाऐंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार के विभागों और दिल्ली पुलिस के संरक्षण में पटाखों की खुले आम बिक्री भी होती है और उन्हें चलाया भी जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मुख्य कारण तीनों लैंड फिलों पर कूड़ा निस्तारण के काम को पूरा करने में विफल रही है जबकि पिछले दो वर्षों से निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है।

उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित को गंभीर होती तो दिल्ली के खतरनाक व जानलेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर वर्ष विंटर एक्शन प्लान बनाने की जरुरत नही पड़ती। सच्चाई तो यह है कि आगामी महीनां में आम आदमी पार्टी का 21 बिंदुओं का विंटर एक्शन प्लान भी खोखला साबित होगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कितने अभियान चला चुकी है परंतु कोई भी कारगर सिद्ध नही हुआ है। गोपाल राय 21 बिंदुओं के विंटर एक्शन प्लान में ऐसा कौन सा अभियान चलाने वाले है जिससे वो दिल्ली के लोगों को जानलेवा प्रदूषण से छुटकारा दिलवाऐंगे।

डॉ. इदरीस कुरैशी दिल्ली राज्य मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के अध्यक्ष नियुक्त

शम्स आगाज

नईदिल्ली: तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार, रविवार को, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत दिल्ली राज्य के अध्यक्षका चुनाव सम्पन्न हुआ। चुनाव की कार्यवाही केंद्रीय कार्यालय में सुबह 10 बजे शुरू हुई, उम्मीदवारों के नाम दोपहर 3 बजे तक सुझाए गए, मुशावरत के सदस्यों द्वारा तीन सुझाव दिए गए थे, लेकिन तीनों में अध्यक्षपद के लिए एक ही नाम प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान दिल्ली के अध्यक्ष सैयद मंसूर आगा ने अगले दो वर्षों के लिए डॉ इदरीस कुरैशी के पक्ष में एलान किया और सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से समर्थन किया। जिसके बाद, निर्वाचन अधिकारी अब्दुल राशिद अंसारी और ऑब्जर्वर मोहम्मद आकिफ ने परिणामों की घोषणा की।

गौरतलब है कि मुशावरत के नियम व क़ायदे के अनुसार, डॉ. इदरीस कुरैशी एक गवर्निंग कॉउंसिल का गठन करेंगे, जिसमे कम से कम 11 सदस्य शामिल होंगे, डॉ. इदरिस कुरैशी को दो वर्ष के लिए दिल्ली राज्य मुस्लिम मुशावरत का अध्यक्ष चुना गया है।

मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज़ अहमद, दिल्ली मुशावरत के पूर्व अध्यक्ष सैयद मंसूर आगा, रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल रशीद अंसारी, पर्यवेक्षक मोहम्मद आकिफ, डॉ. तसलीम रहनी, दिल्ली के पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज़किर खान और मुशावरत के सभी सदस्यों ने बधाई दी।

इस अवसर पर, मुशावरत के राष्ट्रीय अध्यक्षएडवोकेट

फिरोज़ अहमद ने डॉ. इदरीस कुरैशी को बधाई दी और कहा कि दिल्ली राज्य मुशावरत को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए हर संभव तरीके से सहयोग करेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली इकाई और अब तमिलनाडु और केरल में एक मुशावरत इकाई स्थापित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। पुराने और नए सदस्यों को जोड़ने में सैयद मंसूर आगा द्वारा सहयोग किया गया।

दिल्ली राज्य मुशावरत के पूर्व अध्यक्षसैयद मंसूर आगा ने कहा कि डॉ. इदरीस कुरैशी को हमारा हमेशा पूरा समर्थन व सहयोग मिलेगा, जबकि केंद्रीय मुशावरत के वरिष्ठ सदस्य डॉ. तसलीम अहमद रहमानी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के हालात में मुशावरत को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। इस चुनाव प्रक्रिया में केंद्रीय मुशावरत के अलावा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जिसमे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट, ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, मूवमेंट फ़ॉर एम्पावर्मेंट ऑफ मुस्लिम इंडियनस, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी आर्गेनाईजेशन, क़ुरैश कॉन्फ्रेंस (रजि), एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन-केंद्रीय व दिल्ली यूनिट, ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी, यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन, कारवां फाउंडेशन, वॉलंटियर्स ऑफ चेंज, ओखला प्रेस क्लब (रजि.) और अन्य संगठन भी शामिल रहे।

इस अवसर पर, मुशावरत के सदस्य डॉ. मुहम्मद शीश तैमी, डॉ. मुहम्मद फेयाज़, डॉ. जावेद आलम खान, अहमद जावेद, एडवोकेट रईस अहमद, मोहम्मद रईसुल आज़म, मोहम्मद मोइनुद्दीन, डॉ. नबील सिद्दीकी, मोहम्मद इलियास सैफी, मौलाना निसार अहमद हुसैनी-अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग-दिल्ली स्टेट, आसिफ अंसारी-राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ज़ीशान खलीक, इमलाक अहमद, शेख यामीन कुरैशी, रईस आज़म खान, अज़ीज़ुर -रहमान राही, मेहताब आलम, डॉ. सैयद मुहम्मद फैसल, मोहम्मद मोईनुद्दीन हबीबी, मोहम्मद फैज़ान रहमान, मोहम्मद मोइनुल हक खान, अब्दुल जब्बार, मोइन कुरैशी, रईस अहमद, अधिवक्ता मोहम्मद तेयब खान, असलम अहमद (अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट), बद्र आफाक़, डॉ. अतहर इलाही खान, शेर मोहम्मद, मसरूर हसन सिद्दीकी अधिवक्ता, सैयद रोमान हाशमी, डॉ. एम. अथरुद्दीन (मुन्ने भारती), अजमेरी सोहेल, मलिक तहसीन अहमद, मोहम्मद इरफान, सनोबार अली एडवोकेट, अब्दुल रहमान, मोहम्मद आतिफ, सैयद इशरत अली, मोहम्मद खालिद, मुदस्सर हयात और कबीर खान इत्यादि मौजूद थे।

विश्वविद्यालय के सभागार में सरताज की मधुर आवाज पर झूमे हजारों फैंस

सुषमा रानी

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के सभागार में पंजाबी के विश्व विख्यात गायक सतिंदर सरताज ने सुरों की ऐसी तान छेड़ी कि शाम यादगार हो गई। इस इवेंट का सरताज के फैंस को मुद्दत से इंतजार था , आलम यह था कि दिल्ली सरताज फैंस क्लब के प्रमुख दीपक बजाज करीब चालीस से ज्यादा फैंस के साथ इस शो को देखने और अपने प्रिय गायक से रूबरू होने के लिए गए।

शो शुरू होने के बाद अपने झूमते फैंस की फरमाइश पर सरताज ने इश्के दे अंबरी उडारियां गीत जब पेश किया तो दीपक के साथ दिनेश बजाज ,ऋषि मदान मोहित छाबड़ा सुदर्शन आदि सरताज के पक्के फैंस हाथों में उनकी फोटो लिए नाचने लगे। हर कदम थिरकने लगा।

इससे पूर्व एडीसी वैशाली सिंह, एसडीएम आशीष कुमार, मठ के महंत बाबा बालक नाथ ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। गायक के मंच पर आते ही श्रोताओं के साथ दीपक और उनके साथियों ने अपने चहेते कलाकार को उपहार भी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद गायक ने एक के बाद एक गीतों की शानादार प्रस्तुति दी। सरताज ने एक के बाद एक गीतों की शानादार प्रस्तुति दी। हर गीत के साथ श्रोता का

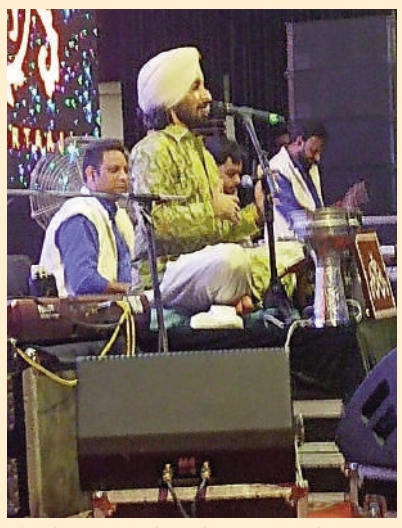

जोश देख सरताज ने अपने सुपर हार्ट गाने प्यार होंदा फूलां तो अनूक सोणया, सजन राजी हो जावे, इत्रां दी शीशी, तेरी मेरी यारी सहित कई गाने पेश किए ।मंच पर फ्यूजन बैंड के कलाकारों ने राग भैरवी की प्रस्तुति दी। इस शो के दौरान ।सभागार के बाहर खड़े सरताज के हजारों फैंस उनकी एक झलक पाने को खड़े रहे।

शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान-वित्त मंत्री आतिशी

सुषमा रानी

नईदिल्ली। 54वें जीएसटी काउंसिल बैठक में केजरीवाल सरकार के विरोध के बाद अब रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली व पंजाब सरकार के जीएसटी काउंसिल में विरोध पर केंद्र सरकार रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए राज़ी हो गई है।

इस बाबत साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, जीएसटी काउंसिल ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ना लगाने का फ़ैसला लिया है, यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि, शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फ़ैसला रिसर्च के ज़रिए देश की तरक्क़ी में योगदान देने वाले हमारे शैक्षिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला साबित होगा।

वित्त मंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए भी कहा कि, आम आदमी पार्टी ने लगातार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि शिक्षण संस्थानों को मिली रिसर्च ग्रांट - चाहे वो सरकारी ग्रांट हो या प्राइवेट - पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मुझे ख़ुशी है कि आज जीएसटी काउंसिल ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ना लगाने का फ़ैसला लिया है। यह देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, आज जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर लगने वाले जीएसटी का पुरज़ोर विरोध किया।

उन्होंने कहा कि, शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगना टैक्स टेररिज्म के समान है। और हमें इस बात की ख़ुशी है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बाक़ी राज्य सरकारों की सहमति बनी।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, जो मुद्दा बार बार दिल्ली सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उठा रही थी कि, रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए उसपर आज जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अब किसी शैक्षिक संस्थान को मिलन वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि, ये रिसर्च के ज़रिए देश की तरक्क़ी में योगदान देने वाले हमारे शैक्षिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला है।

क्या था रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मुद्दा

बता दे कि, शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले प्राइवेट रिसर्च ग्रांट पर केंद्र सरकार 18% जीएसटी लेती है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर 220 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा था ।दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च पर जीएसटी लगाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने इसका पुरज़ोर विरोध किया और नतीजतन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से हटाने का फ़ैसला लिया है।

वीके सक्सेना दिल्ली के सबसे अक्षम एलजी, उनसे नहीं संभल रही कानून-व्यवस्था, इस्तीफा दें- प्रियंका कक्कड़

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त एलजी वीके सक्सेना पर तीखा हमला बोला। ''आप'' की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वीके सक्सेना दिल्ली में अब तक के सबसे अक्षम एलजी हैं। उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। लिहाजा उन्हें अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकार छीनने में व्यस्त एलजी साहब का पुलिस सुधार पर कोई ध्यान नहीं है। इसी वजह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते छह सितंबर को सीमापुरी के एक क्लब में बदमाशों द्वारा सरेआम की गई कई राउंड फायरिंग ये बताती है कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था भगवान भरोसे है। यहां सरेआम फायरिंग, लूटपाट और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन भाजपा के एलजी साहब और केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वहीं, अब तो एलजी साहब सोशल मीडिया पर भी पैसे खर्च कर रहे हैं। इसलिए उनको ये बताना चाहिए कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि 6 सितंबर को देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाली घटना घटित हुई। इस घटना की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में चार अपराधी बंदूक लेकर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी स्थित एक क्लब में उगाही करने गए। बदमाशों ने क्लब के बाउंसर को घुटनों के बल बैठने के लिए कहा और सरेआम कम से कम 12 राउंड फायरिंग की।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले, बीते 15 जुलाई को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में अपराधी घुसे और वहां इलाज करा रहे मरीज को बंदूक भून दिया। पिछले साल 26 जून को प्रगति मैदान में टनल पर दिन दहाड़े चार बाइक सवार बदमाशों ने एक कार को घेरकर उसके चालक को लूट लिया। जंगपुरा में लूटपाट के दौरान बुजुर्ग डॉक्टर की मृत्यु हो गई। जंगपुरा में ही एक जूलरी शॉप से 24-25 करोड़ रुपए लूट लिए गए। वहां भी सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जब से दिल्ली में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली है, तब से कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि प्रति एक लाख की आबादी पर 1832 अपराध होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े एक बहुत चौकाने वाला तथ्य भी रखता है कि मात्र 30 फीसद केस में ही चार्जशीट होती है। मसलन, जब जेएनयू में हिंसा हुई तो कोमल शर्मा को पुलिस ने न तो गिरफ्तार किया और ना ही चार्जशीट की, क्योंकि कोमल शर्मा भाजपा छात्र विंग की सदस्य थीं।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के अधीन जहां भी कानून व्यवस्था है, वहां कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। चाहे मणिपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हो, हर जगह कानून व्यवस्था बुरी तरह खराब हो चुकी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी के अधीन आती है। हरियाणा में भी भाजपा ने एक गैंगस्टर की पत्नी को टिकट दिया। भाजपा बार-बार अपराधियों को संरक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाती है। पुलिस में सुधार को लेकर दिल्ली के एलजी ने क्या कदम उठाए, कितनी पीसीआर बढ़ाई, पुलिस में भर्ती की, पुलिस कमिश्नर से बैठक की, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े ये साफ दर्शाते हैं कि वीके सक्सेना दिल्ली के सबसे असफल (अक्षम) एलजी हैं। कानून व्यवस्था उनसे संभलती नहीं है। एलजी वीके सक्सेना दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने में ही व्यस्त रहते हैं और दिल्ली सरकार के अच्छे काम में फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं।

"मिच्छामी दुक्कड़म"

आओ मिटाए जाति, धर्म का भेद,
अपनी गलतियों पर व्यक्त करें खेद।
ये दो शब्द ₹मिच्छामी दुक्कड़म₹
विशेष हैं सभी को याद रहे हरदम।
ज़ब शब्दों, कर्मों या विचारों से,
हुई हो किसी भी प्रकार की पीड़ा।
गलती से भी पैरों में आकर,
अस्तित्व से मिट गया हो कोई कीड़ा।
इस पवित्र अवसर पर हृदय से,
उन सभी से क्षमा मांग उठाओं बिड़ा।
करो त्याग अहंकार की भावना,
कर लो सच्चे मन से क्षमा की कामना।
सच्ची शांति और सुख संभव तभी,
करों एक-दूजे को क्षमा का साहस सभी।
दिलों में प्रेम और करुणा का हो भाव,
जलाओ ज्योत प्रेम की हर-घर में हो छांव।

एक जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रहेगा प्रतिबंध- गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना के मद्देनजर सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने पिछले साल भी सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है और यह प्रतिबन्ध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। साथ ही प्रतिबन्ध को कड़ाई से लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनायी जाएगी।

पटाखों के पूर्ण प्रतिबन्ध के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है। इस मौसम में पटाखों को जलाने से भी प्रदूषण बढ़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा

है, जिससे लोगों को प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। किसी भी तरह के पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी या बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखों को लेकर लोगो में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न न रहें, इसलिए यह प्रतिबन्ध हर तरह के पटाखों के लिए मान्य है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में लागू रहेगा, ताकि पटाखों के जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से दिल्लीवासियों को निजात दिलाई जा सकें।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती है कि व्यापारियों और डीलरों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान हो। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए समय रहते हर प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंध को कड़ाई से दिल्ली में लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है। आगामी दिनों में विंटर एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में हमारी दिल्ली निवासियों से अपील हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ सहभागिता दें। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम सभी को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि दिल्ली का हर नागरिक एक प्रदूषण योद्धा बन कर पर्यावरण को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लेगा तो प्रदूषण के कारण लोगों की सांसो पर जो संकट आता है, उससे हम उन्हें बचा सकेंगे। हम दिल्लीवासियों से यही कहना चाहते है कि दीए जलाकर और मिठाई बाँटकर त्योहार मनाएं। हमें त्योहार को धूमधाम से मनाना है लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी से प्रदूषण पर भी लगाम लगाना है।

दिल्ली में पटाखे बैन करने पर व्यापारियों में रोष - परमजीत सिंह पम्मा

सुषमा रानी

दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखे की बिक्री और चलने पर रोक को लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने नाराजगी जताई है। पम्मा ने कहा नेताओं की रैलियां में वह हर जगह पटाखे चला सकते हैं मगर जब दिवाली या अन्य त्योहार आते हैं तो पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। इसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। जबकि अन्य राज्यों से दिल्ली में पटाखे लाकर खुलेआम चलाए जाते हैं। पम्मा ने कहा बड़े दुख की बात है दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम ने पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई भी करें तो किया नहीं है मगर यह पटाखे बेन करके अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि सड़कों पर इतना गंद होता है इतना कूड़ा खुलेआम होता है। कोई सफाई का प्रबंध नहीं होता। किसी प्रकार का इन्होंने पॉल्यूशन रोकने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। और थोड़े दिन बाद यह ओड एंड इवन को भी ले आएंगे।

कांग्रेस ने दो सीटों पर चला बड़ा दांव, पार्टी ने बैठाया ऐसा गणित; उम्मीदवार को मिलेगा फायदा

कांग्रेस (Congress) पार्टी हरियाणा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी एक-एक सीट को लेकर पूरी रणनीति के साथ उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। अब कांग्रेस ने इन दो सीटों पर बड़ा दांव चला है। पार्टी दोनों सीटों पर ऐसा गणित बैठाया है कि उम्मीदवारों को अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। पढ़िए आखिर कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है?

गुरुग्राम। कांग्रेस पार्टी ने गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से टिकट के दावेदारों का इंतजार खत्म कर दिया। पार्टी ने गुड़गांव सीट से पंजाबी नेता और हाल ही में कांग्रेस में आए मोहित ग्रोवर एवं बादशाहपुर से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वर्धन यादव को टिकट दिया है। दोनों ही युवा नेता हैं और अपने-अपने क्षेत्र में इनकी सक्रियता है। कांग्रेस हाईकमान ने दोनों सीटों से जातीय समीकरण को भी साधा है।

Haryana Election चुनाव में दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अभी पटौदी और सोहना सीट से प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। गुड़गांव विधानसभा सीट पंजाबी बहुल मानी जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र में इस समय 4,30,893 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा पंजाबी, फिर बनिया, ब्राह्मण, यादव और जाट समाज के मतदाता हैं।

वहीं, 2019 विधानसभा चुनाव में भी मोहित ग्रोवर निर्दलीय मैदान में थे। भाजपा (BJP) प्रत्याशी सुधीर सिंगला 81953 वोटों के साथ जीते थे और मोहित ग्रोवर को 48638 वोट मिले थे। मोहित चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। बीते 15 साल से कांग्रेस इस सीट से दूर है। इस बार वह मोहित ग्रोवर के माध्यम से पंजाबी वोटों के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश में है।

मोहित की राह आसान नहीं होगी

गुड़गांव सीट से टिकट के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, वरिष्ठ नेता पंकज डावर, कांग्रेस राष्ट्रीय कमेटी के सचिव अशीष दुआ, कुलराज कटारिया, कुलदीप कटारिया, सीमा गुप्ता आजाद, खुशबू मंगला शर्मा, गजे सिंह कबलाना, सुनीता सहरावत, डॉ. मुकेश शर्मा, सूबे सिंह यादव समेत 32 नेताओं ने दावेदारी की थी। मोहित ग्रोवर 20 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे में टिकट मिलने के बाद मोहित की राह आसान नहीं होगी। उन्हें टिकट के दावेदारों को साथ लेकर चलने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

वर्धन यादव पहली बार मैदान में

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राहुल गांधी के करीबी नेता वर्धन यादव की बादशाहपुर क्षेत्र में अच्छी पहचान है। यह सीट यादव बहुल मानी जाती है। उनकी पत्नी कोमल कथूरिया पंजाबी समाज से हैं। ऐसे में वर्धन यादव को इस क्षेत्र से यादव के साथ-साथ पंजाबी समाज के वोट बैंक को भी साधने में मदद मिलेगी। वर्धन यादव पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं। इनकी राजनीति की शुरुआत 2009 में हुई थी।

इन्होंने 2009 में कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआइ का दामन थामा। 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा। उसके बाद इनका प्रवेश 2014 में भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस में हुआ। 2014 से 2017 तक एनएसयूआइ के राष्ट्रीय सचिव रहते हुए वर्धन यादव ने कम समय में पहचान बनाई। वर्धन ने असम, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एनएसयूआइ का प्रभारी रहकर संगठन को मजबूत करने का काम किया।

वहीं, 2021 से राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। बादशाहपुर इलाके में इनकी सक्रियता की वजह से हाईकमान ने इन पर दांव खेला है। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री नरबीर सिंह मैदान में हैं। ऐसे में वर्धन की जीत की राह आसान नहीं होगी।

उधर, बादशाहपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिरेंद्र सिंह यादव, इंटक प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता चौधरी संतोख सिंह, प्रदीप सिंह जेलदार समेत 17 नेताओं ने दावेदारी की थी।

गाजियाबाद में अब 13 तरह की नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लेना होगा लाइसेंस, नगर निगम की बैठक रखा जाएगा प्रस्ताव

गाजियाबाद नगर निगम ने 13 नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इनमें जिम ब्यूटी पार्लर कोचिंग सेंटर प्रशिक्षण संस्थान सीए कार्यालय स्पा सेंटर ज्वैलरी शोरूम ब्रांडेड कपड़े और जूतों के शोरूम स्पोर्ट्स अकादमी आदि शामिल हैं। यह कदम राजस्व बढ़ाने और शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। जीडीए की बैठक में प्रस्ताव पास होते ही लागू होगा।

गाजियाबाद।: गाजियाबाद में 13 तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए आने वाले दिनों में नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नगर निगम व्यवसायों को 13 श्रेणी में बांटकर नीति बना ली है। आगामी नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड बैठक में हरी झंडी मिलने ही यह लागू हो जाएगा।

दरअसल, अभी 39 श्रेणी के कारोबार करने के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस जरूरी है जिसमें होटल, लांज, रेस्तरां, शराब के ठेके, निजी अस्पताल, फाइसेंस कंपनी, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर मुख्य रूप से शामिल है। नगर निगम अधिकारियों ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए कुछ व्यवसाय की श्रेणियों की दरों में संशोधन किया है।

13 श्रेणियों के व्यवसाय ट्रेड लाइसेंस के दायरे में आएंगे

इसके अलावा 13 अन्य श्रेणियों के व्यवसाय को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि नई व्यावसायिक श्रेणियों में जिम, ब्यूटी पार्लर कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान, सीए कार्यालय, स्पा सेंटर, ज्वैलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़े ओर जूतों के शोरूम, स्पोर्ट्स अकादमी आदि को शामिल किया गया है।

गजब! पति हो तो ऐसा: पत्नी को दिलाई दुनिया में पहचान, भारत का गौरव बनीं सिमरन; दिलचस्प है दोनों की प्रेम कहानी

पति और पत्नी का रिश्ता अगर दिल से निभाया जाए तो वह मिसाल बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली सिमरन और उनके पति गजेंद्र का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों ने 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पढ़िए दोनों की दिलचस्प स्टोरी।

गाजियाबाद। मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है, मैं कैसे हार मानकर थक जाऊं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक हैं। यह पंक्तियां मोदीनगर की सिमरन शर्मा पर सटीक बैठती हैं। छोटी सी उम्र में आंखों की रोशनी न होने के बावजूद आज उन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया।

सिमरन के लिए यह राह आसान नहीं थी, लेकिन उनके हौसले, कठिन परिश्रम और लगन से यह संभव हो सका। उन्होंने अपनी कमजोरी को सफलता के आगे नहीं आने दिया। उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर पेरिस पैरालिंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया।

मूलरूप से मोदीनगर के गोयलपुरी की रहने वाली सिमरन तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं। भाई आकाश निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। बहन अनुष्का की शादी हो चुकी हैं। पिता की चार साल पहले मौत हो गई थी। करीब छह साल पहले सिमरन की मोदीनगर तहसील के गांव खंजरपुर में गजेंद्र के साथ शादी हुई थी। यह प्रेम विवाह था। गजेंद्र सेना में हैं। उनकी दिल्ली में तैनाती हैं। उनके साथ ही सिमरन भी पिछले चार साल से दिल्ली में रह रही हैं।

बताया गया कि पति गजेंद्र ने ही उन्हें दौड़ का प्रशिक्षण दिया। पति के साथ कोच की भी भूमिका निभाई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सिमरन प्रशिक्षण लेती थीं। सिमरन उन लोगों के लिए नजीर बनी हैं जो अपनी दिव्यांगता को कमजोरी मानकर राह से हट जाते हैं। सिमरन अपने मजबूत इरादों से लगातार सफलता हासिल कर रही हैं।

मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर पेरिस तक का सफर

सिमरन के पिता मनोज शर्मा अस्पताल में चिकित्सक के पास नौकरी करते थे। मां सविता हॉस्टल में टिफिन सप्लाई करती हैं। परिवार की आय सीमित थी। रूक्मिणी मोदी इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की। कॉलेज में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेती थी। 12वीं के बाद खेलों में ही करियर की राह चुनी।

सिमरन के भाई आकाश ने बताया कि वह साइड में नहीं देख सकती हैं। सामने भी कुछ ही दूरी तक सिमरन को दिखता है। इसके बावजूद वह अपने काम को लेकर गंभीर रहती हैं। उसने आत्मनिर्भरता के साथ सभी काम किए।

24.75 सेकंड में की 200 मीटर पार

सिमरन शर्मा ने पेरिस पैरालिंपिक में महिला की 200 मीटर टी-12 स्पर्धा में 24.75 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। सिमरन दृष्टिहीन हैं और एक गाइड के साथ दौड़ती हैं। बचपन में उनकी विकलांगता के कारण उन्हें बहुत परेशान किया जाता था।

एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले लोगों के DNA में अपराध, CM योगी के मंत्री का बयान

यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और जो कोई राजनीति कर रहे हैं उनके बार में जगजाहिर है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में गुंडे अपराधी माफिया जिले के कप्तान और थाने के दारोगा को निर्देशित करने का कम करते थे।

नोएडा। यूपी सरकार के मंत्री ने एनकाउंटर पर सवाल उटाने वालों पर निशाना साधा है। सेक्टर-62 में आइकिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा पिछली सरकारी केवल अपने, अपने परिवार और अपनी बिरादरी तक सीमित थी। सुल्तानपुर के एनकाउंटर को लेकर कहा, कि अपराधी की कोई जाति नहीं है। जो कोई राजनीति कर रहे हैं उनके बार में जगजाहिर है।

अपराधी की जाति आधार कार्ड देखकर तय नहीं होती। पहले की सरकारों में गुंडे, अपराधी, माफिया जिले के कप्तान और थाने के दारोगा को निर्देशित करने का कम करते थे। आज कानून को हाथ में लेने पर पुलिस उन्हें उनकी भाषा में जवाब देती है।

सपा पर साधा निशाना

एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले लोगों के डीएनए में अपराधी और अपराध भरा हुआ है। पहले जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा की धारणा थी। सरकार में एक जिला एक, माफिया पैदा होते थे। आज एक जिला एक उत्पाद की धारणा बनी है। उत्तर प्रदेश में रिकार्ड तोड़ निवेश हो रहा है। सबका निवेश सुरक्षित रहे इसकी गारंटी सरकार ले रही है।

सीएम योगी ने किया लिक्ली स्टोर का शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ से वर्चुअल जुड़कर आइकिया की ओर से सेक्टर-51 में निर्मित होने वाले रिटेल स्टोर, होटल, मीटिंग स्पेश, शापिंग सेंटर का शिलान्यास किया। उन्होंने इंग्का सेंटर्स के लिक्ली स्टोर के मॉडल का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि 47,833 वर्ग मीटर में 5,500 करोड़ की लागत से बनने सेंटर से नौ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 9.2 प्रतिशत का अपना योगदान दे रहा है।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी।

अतीत और वर्तमान, बाधाओं से जूझती रही हिंदी

उमेश चतुर्वेदी

राजभाषा के नाम पर इस रस्म को आयोजित होने की परंपरा को विकसित करने में संविधान सभा के उस विधान की बड़ी भूमिका रही, जिसके तहत हिंदी को संविधान लागू होने से पंद्रह वर्षों तक के लिए टाल दिया गया।

हिंदी की जब भी चर्चा होती है, दो तरह के भाव आते हैं। इसे लेकर पहला भाव उत्साह और गर्वबोध वाला होता है। हिंदी के क्षितिज के लगातार हो रहे विस्तार और उसके गर्वीले अतीत को लेकर हिंदीप्रेमी जहां उत्साह से भर उठते हैं, वहीं अंग्रेजी माध्यम से पढ़े गुलामी की मानसिकता वालों के चेहरे पर विद्रूप और व्यंग्यभरी मुस्कान चिपक जाती है। दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों के राजनीतिक तो हिंदी से अछूत जैसा व्यवहार करने में स्वयं जहां गर्वबोध का अनुभव करते हैं, वहीं अपने समर्थकों को हिंदी को दुश्मन की तरह मानने के लिए उकसाने में भी पीछे नहीं रहते। इसके बावजूद हिंदी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, विशेषकर आमजन की बोली-बानी के रूप में यह स्थापित होती जा रही है। इतने सारे विरोध के बावजूद और अड़ंगे के बावजूद हिंदी अगर बढ़ती नजर आ रही है तो मानना पड़ेगा कि उसमें कुछ बात जरूर है। हिंदी के इस प्रभावी हश्र पर इकबाल की पंक्तियां याद आना स्वाभाविक है,

कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी।

सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-ज़माँ हमारा।।

हिंदी की राह में आजादी के पहले ज्यादा बाधाएं नहीं थीं। इसकी शायद यह बड़ी वजह रही कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अगुआ महात्मा गांधी स्वयं हिंदी के हिमायती थे। उनके पहले केशव चंद्र सेन, लोकमान्य तिलक जैसी हस्तियां भी देश के हृदयों को नजदीक लाने में हिंदी की सामर्थ्य को पहचान चुके थे। इसीलिए गैर हिंदीभाषी होने के बावजूद उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की केंद्रीय भाषा हिंदी को बनाने की कोशिश की और भावी भारत की भाषायी जरूरतों के लिहाज से हिंदी को तैयार करने की कोशिश भी की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसी संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य हिंदी को भावी भारत की भाषायी जरूरत के लिहाज से ना सिर्फ तैयार करना था, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच मजबूत सेतु के रूप में स्थापित करना भी था। हिंदी इस दिशा में आगे बढ़ती रही। कांग्रेस के दस्तावेज भले ही अंग्रेजी बनते रहे, लेकिन बहसों और उसके वार्षिक अधिवेशनों की भाषा हिंदी ही रही। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद हिंदी के इस प्रभाव को सुभाष चंद्र बोस ने भी समझा और बाकायदा हिंदी सीखी। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते पार्टी के वार्षिक अधिवेशन को उन्होंने हिंदी में ही संबोधित किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के आर्काइब में आज भी सुरक्षित है। उनकी मीठी हिंदी एक तरह से मोहती है। उसे सुन लगता है कि स्वाधीनता संग्राम में हिंदी किस तरह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी।

जिस हिंदी का ऐसा इतिहास रहा हो, जिसे विनोबा जैसे संघर्षशील और त्यागी-तपस्वी व्यक्ति ने अपनी भाषायी तपःसाधना का माध्यम बनाया हो, उसे स्वाधीनता के बाद तेजी से विस्तारित होना चाहिए था। वह विस्तारित तो हुई, लेकिन उस रूप में स्थापित नहीं हुई, जिस रूप में स्वाधीनता सेनानियों ने सोचा था। राजभाषा की उसे पदवी तो मिली, लेकिन वह रस्मी ही साबित हुई। राजभाषा की भूमिका सरकारी दफ्तरों में सिर्फ हिंदी पखवाड़े या महीने में कार्यालयों में रस्मी निबंध, कहानी और कविता प्रतियोगिता आयोजित करने और किसी हिंदी विद्वान को बुलाकर उंघते और उबते कर्मचारियों के बीच भाषण कराने तक सीमित रह गई। हिंदी दिवस पाखंड बन कर रह गया। अच्छी बात यह कह सकते हैं कि इस बहाने सरकारी कार्यालयों के कुछ कर्मचारियों को कुछ नगद रकम बतौर पारितोषिक मिल जाती है, और बाकी कर्मचारियों को मिठाई और नाश्ता आदि और फिर हिंदी की पूरे वर्षभर के लिए राजभाषा के रूप में इतिश्री हो जाती है।

राजभाषा के नाम पर इस रस्म को आयोजित होने की परंपरा को विकसित करने में संविधान सभा के उस विधान की बड़ी भूमिका रही, जिसके तहत हिंदी को संविधान लागू होने से पंद्रह वर्षों तक के लिए टाल दिया गया। कहा गया कि इतने दिनों में हिंदी राजकाज में स्थापित अंग्रेजी का स्थान लेने लायक हो जाएगी। लेकिन इसी बीच अंग्रेजी समर्थकों, हिंदी विरोधी कहना ज्यादा समीचीन होगा, ने हिंदी के खिलाफ षडयंत्र जारी रखा। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी को हिंदी की तुलना में ज्यादा गंभीर और प्रभावी रूप से स्थापित किया। इतना नहीं, इस बीच हिंदीतर दूसरी भारतीय भाषाओं के मन में हिंदी को लेकर लगातार जहर भरा जाता रहा। इसमें अंग्रेजी शिक्षा और उसके जरिए मिलने वाली सुख-सुविधाएं और बेहतर नौकरियों ने बड़ा योगदान दिया। अगर आजादी के तुरंत बाद हिंदी को लागू कर दिया जाता और हिंदी को विकसित करने के तर्क को परे सरका दिया गया होता तो आज हिंदी कुछ उसी तरह स्थापित होती, जैसे इंडोनेशिया और तुर्की में हुआ। इसे संयोग ही कहेंगे कि भारत से ठीक दो वर्ष पहले 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया डच शासन से मुक्त हुआ था। तब तक इंडोनेशिया के राजकाज की भाषा डच होती थी। लेकिन आजादी मिलते ही इंडोनेशिया के शासक सुकर्णो ने तुरंत अपनी भाषा 'बहासा इंडोनेशिया' को लागू कर दिया। कुछ इसी तरह 23 अक्टूबर 1923 को जब आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई, तब वहां के स्वाधीनता सेनानी और शासक कमाल अतातुर्क ने तत्काल तुर्की भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में लागू कर दिया। अगर भारत में भी कुछ हिंदी के साथ ऐसा ही हुआ होता तो निश्चित तौर पर इतिहास और परिदृश्य दोनों अलग होते।

स्वाधीन भारत से एक और गलती हुई है। वैसे इसे गलती मानें या जानबूझकर रचा गया हिंदीविरोधी षड्यंत्र कहें। स्वाधीन भारत की नौकरशाही की भाषा अंग्रेजी ही रही। या यूं कहें कि हिंदी या भारतीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए ऐसी राह तैयार की गई कि वे ही नौकरशाही में आ सकें। भारतीय भाषाओं को संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनाने के लिए आंदोलन चला तो उसके दबाव में भारतीय भाषाएं आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनीं तो लेकिन परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया का ढांचा ऐसा बना रहा कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र ही ज्यादा चुने जाते रहे। हिंदी या भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित इक्का-दुक्का विद्यार्थी अगर नौकरशाही में प्रवेश पाने में सफल रहे भी तो उनकी स्थिति 'नक्कारखाने में तूती की आवाज' जैसी रही। नरेंद्र मोदी के उभार और मोदी-शाह की जोड़ी के हिंदी प्रेम के चलते नौकरशाही में हिंदी के प्रति रूझान दिखा। नौकरशाही की भाषायी सोच में परिवर्तन आता दिखा भी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वह नौकरशाही की रणनीतिक चाल रही। नौकरशाही ने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करने के लिए भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम का संकेतभर दिया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। हिंदी और भारतीय भाषाएं राजकाज में एक बार फिर पीछे हो गई हैं। अंग्रेजी अब भी नौकरशाही और राजकाज में वर्चस्व बनाए हुए है। उसके मनोभाव उसके इरादे को एक बार फिर जाहिर करने लगे हैं। वह एक बार फिर हिंदी पर अंग्रेजी को ही उपर रखने लगी है। राजकाज एक बार फिर पुरानी पटरी पर कम से कम भाषायी लिहाज से लौटने लगा है। हिंदी को लेकर ऐसा रूख नौकरशाही अगर दिखाती है तो इसकी वजह हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच की आपसी खींचतान के साथ ही शासन की रस्मी भाषा नीति भी है।

हिंदी की राह में यूं तो कई बाधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा शासन में उसकी उपेक्षा और अंग्रेजीदां नौकरशाही का वर्चस्ववादी रवैया है। इस रवैये का नुकसान ज्यादातर जमीनी नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। क्योंकि उनकी समस्याओं को सही मायने में समझने वाली ब्यूरोक्रेसी ही नहीं है। यह मोटा तथ्य है कि किसी व्यक्ति या इलाके की समस्याओं को वही गहराई से समझ सकता है, जो उस व्यक्ति की अपनी भाषा में सोचता हो, उस इलाका विशेष की माटी की संस्कृति से जुड़ा हो। लेकिन इसे उलटबांसी ही कहेंगे कि ज्यादातर नौकरशाही ऐसी सोच से कोसों से दूर है। इसीलिए हिंदी समेत भारतीय भाषाएं राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी से कोसों पीछे हैं। उच्च स्तर पर प्रभाव के लिहाज से भी हिंदी का स्थान कुछ खास नहीं है। हिंदी दिवस पर क्या हम इस नजरिये से हिंदी की स्थिति को देखेंगे? वक्त आ गया है कि इस सवाल से गंभीरता से जूझा जाए।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्यों हैं जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य हैं और इसी के मद्देनजर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के साथ-साथ परिवहन के विभिन्न साधनों के इलेक्ट्रिकीकरण पर जोर बढ़ रहा है। पड़ोसी देश चीन में बिकने वाले आधे से ज्यादा वाहन इलेक्ट्रिक हैं और भारत में भी ईवी को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए निजी और सरकारी प्रयास जारी हैं। ईवी की तरफ बढ़ता रुझान सिर्फ एक फैशन नहीं, बल्कि एक जरूरी बदलाव है, जो देश के भविष्य की बेहतरी से जुड़ा है।

इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे वह कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, तिपहिया वाहन हो या बस-ट्रक हो, चलते समय कोई हानिकारक गैस उत्सर्जित नहीं करते। इससे वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। पेट्रोल-डीजल वाहनों से होने वाला प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। इलेक्ट्रिक वाहन इस समस्या को कम करने में मदद करेंगे।

भारत में कोयले का भंडार है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली पैदा करके हम विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। साथ ही विदेशी तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इलेक्ट्रिक वाहन हमें इस अस्थिरता से बचाएंगे।

देश भर में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन

निर्माण संयंत्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में कई नए रोजगार सृजित होंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख निर्यातक बन सकता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी।

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में लगातार नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। इससे भारत तकनीकी रूप से उन्नत देश बन सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर भारत दुनिया में पर्यावरण के प्रति जागरूक देश के रूप में उभरेगा, जो समय की मांग है।

इलेक्ट्रिक वाहन बहुत शांत होते हैं और उनमें कंपन भी कम होता है, जिससे राइडिंग का अनुभव बेहतर होता है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में चलने वाले हिस्से कम होते हैं, जिससे उनका रखरखाव कम खर्चीला होता है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हैं। इनसे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियां बनानी चाहिए और निजी क्षेत्र को भी इसमें अधिक निवेश करना चाहिए। इन सबके बीच यह भी जरूरी है कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वे पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करें। ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना भी जरूरी है।

सब्सिडी के बिना भी इलेक्ट्रिक वाहन लागत को बनाए रख सकते हैं, लेकिन प्रोत्साहन का विरोध नहीं करेंगे: नितिन गडकरी

परिवहन विशेष न्यूज

सोमवार, 09 सितंबर को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बयान दिया है। अपने बयान में नितिन गडकरी ने बताया है कि लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में गिरावट हुई है। इस गिरावट के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। अब बिना सब्सिडी दिए भी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां अपनी लागत की कीमत को बरकरार रख सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये फैसला वित्त तथा भारी उद्योग मंत्रालयों का होगा कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना चाहते है या नहीं।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी एक्मा के वार्षिक सत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दो वर्ष के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल तथा डीजल वाहनों के बराबर हो जाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने की दर अपेक्षा के अनुरूप न होने के कारण इसे बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता पर किए सवाल पर उन्होंने कहा, '' सबसे पहले, मैं किसी सब्सिडी के खिलाफ नहीं हूं। मुझे कोई समस्या नहीं है।''

अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय लिथियम आयन बैटरी की कीमत 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट घंटा थी। अब इसकी कीमत कुछ 10.8 से 11 करोड़ प्रति किलोवाट घंटा है। उन्होंने कहा, '' मुझे विश्वास है कि यह 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी।''

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में मात्रा की दृष्टि से वृद्धि देखी गई है। गडकरी ने कहा, '' मेरा आकलन है कि सब्सिडी के बिना भी आप ईवी की उस लागत को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि उत्पादन लागत कम है।'' उन्होंने कहा, '' मुझे लगता है कि दो साल के भीतर पेट्रोल वाहन तथा डीजल वाहन की लागत इलेक्ट्रिक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर बचत हो रही है।'' इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के मुद्दे पर गडकरी ने कहा कि यदि वित्त मंत्री और भारी उद्योग मंत्री सब्सिडी देना चाहते हैं तो यह मोटर वाहन उद्योग के लिए फायदेमंद होगा।

उन्होंने कहा, '' मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं इसका विरोध नहीं करूंगा।'' मंत्री ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत विश्व में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बन सकता है और कहा कि इस उद्योग का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। उन्होंने कहा, '' मेरा मानना है कि हमें भारत को दुनिया में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बनाना चाहिए।''

गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी में उन्नति, किफायती प्रतिभाशाली कार्यबल की उपलब्धता तथा भारतीय मोटर वाहन उद्योग की वैश्विक स्तर पर अच्छी प्रतिष्ठा जैसे कारक इसके पक्ष में काम करते हैं। पुराने वाहनों को हटाने में तेजी लाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता के सवाल पर गडकरी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि बाजार का रुख मोटर वाहन कंपनियों को उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए स्वयं कदम उठाने को मजबूर करेगा।

बीएमडब्ल्यू को पसंद नहीं आई सरकार की ईवी पॉलिसी, कमियां गिनाईं और कहा- नहीं लगाएंगे पैसा

परिवहन विशेष न्यूज

लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू केंद्र सरकार से नाराज है। कंपनी का कहना है कि उसे इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति पसंद नहीं है। बीएमडब्ल्यू का कहना है कि नीति समान अवसर प्रदान नहीं करती है। सरकार ने उन कंपनियों के बारे में नहीं सोचा है जिन्होंने पहले देश में निवेश किया था। यही वजह है कि बीएमडब्ल्यू नई ईवी नीति के तहत भारत में निवेश नहीं करेगी। बीएमडब्ल्यू ने 2007 में अपना परिचालन शुरू करने के बाद से भारत में 182.5 मिलियन यूरो (1,250 करोड़ रुपये) का निवेश किया है और भारत में इलेक्ट्रिक कारों का आयात कर रही है। जिन कारों का वह आयात कर रही है उनमें बीएमडब्ल्यू आई7, आईX, आई4, आईX1 और मिनी कूपर एसई शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावाह ने कहा, ₹जबकि नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करती है, यह उन कंपनियों की अनदेखी करती है जो लंबे समय से बाजार में हैं।₹ पावाह का मानना है कि सरकार को भारत में शुरुआती चरण की कंपनियों के लिए ईवी नीति में अलग-अलग निवेश मानदंड निर्धारित करने चाहिए, जबकि नए प्रवेशकों के लिए अलग नियम होने चाहिए। उन्होंने कहा, ₹नए खिलाड़ी और मौजूदा कंपनी के लिए न्यूनतम निवेश सीमा अलग-अलग होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पिछले निवेशों को मान्यता मिले। हमें समान अवसर की आवश्यकता है।''

बीएमडब्ल्यू उन कई कंपनियों में शामिल हो गई है, जिन्होंने नई ईवी नीति के तहत भाग लेने से इनकार कर दिया है। सरकार ने अमेरिकी कंपनी टेस्ला को आकर्षित करने के लिए मार्च के मध्य में इस नीति की घोषणा की थी। टेस्ला ने साफ कर दिया है कि भारत आने की उसकी योजना में समय लगेगा। अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी नई ईवी नीति को लेकर सकारात्मक नहीं हैं। इनमें हुंडई, उसकी सहायक कंपनी किआ, मर्सिडीज-बेंज, वोल्वो, टोयोटा, होंडा कार्स और स्टेलेंटिस ग्रुप शामिल हैं। ऑटो उद्योग की ठंडी प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार अब नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि इसे कंपनियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। जल्द ही कुछ संशोधन भी आ सकते हैं।

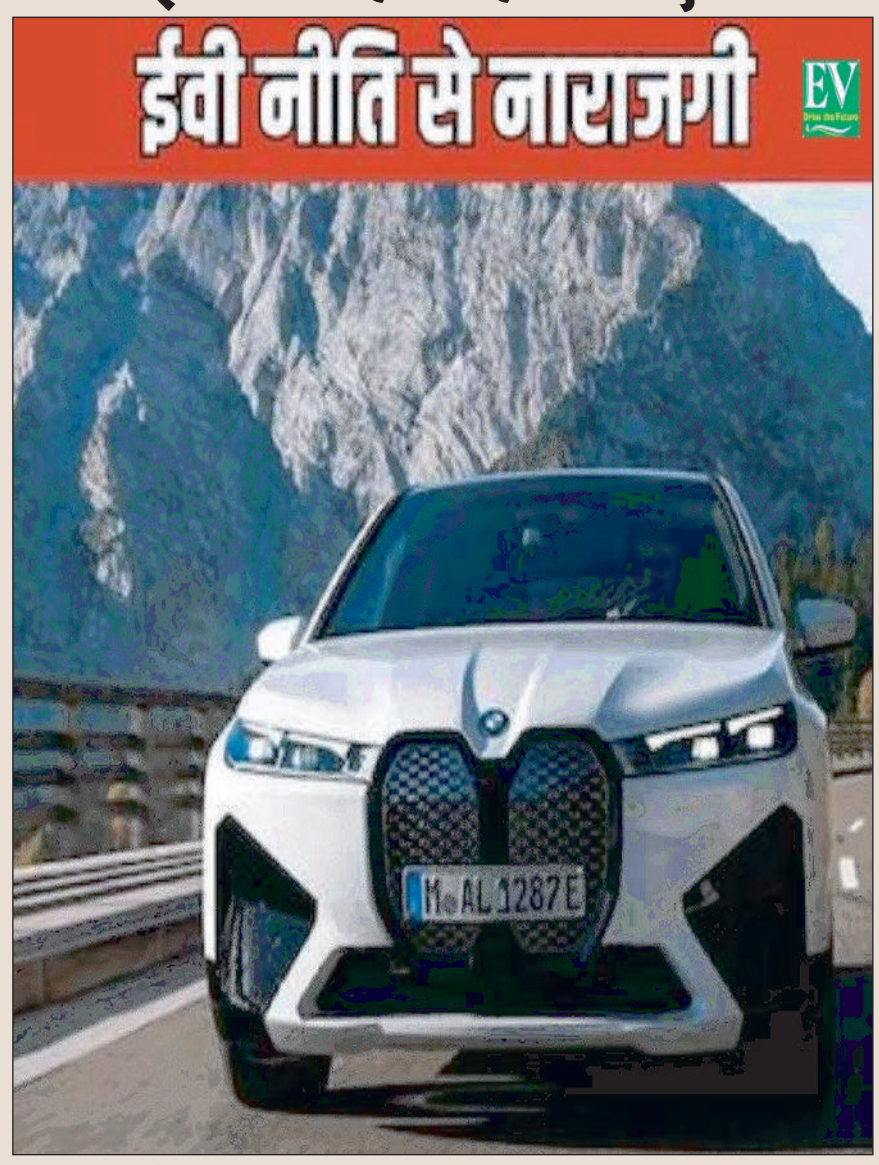

राफ्ट कॉस्मिक ईवी ने विश्व ईवी दिवस पर सौरव गांगुली को ब्रांड एंबेसडर किया घोषित

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की अग्रणी कंपनी राफ्ट कॉस्मिक ईवी ने विश्व ईवी दिवस के अवसर पर दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना नया ब्रांड एंबेसडर घोषित किया। कोलकाता के ताज बंगाल होटल में एक भव्य समारोह के दौरान यह घोषणा की गई।

इवेंट के दौरान राफ्ट कॉस्मिक ईवी ने वॉरियर (स्ट्रीट फाइटर) का नया फेसलिफ्ट वर्जन भी पेश किया। इस नए वर्जन में बेहतर डिजिटल डायल, बड़ा आकार और नई पीढ़ी की मोटर और कंट्रोलर है जो तेजी से प्रतिक्रिया करता है।

इस भव्य समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में कॉस्मिक बिड़ला समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा राफ्ट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सलाहकार आदित्य विक्रम बिड़ला, पूर्व क्रिकेटर एवं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली, मुख्य उत्पाद अधिकारी कुशल चौधरी, मुख्य विपणन अधिकारी राजीव शिशिर नागर और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कुमार सुदर्शन शामिल थे।

आदित्य विक्रम बिड़ला ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ₹राफ्ट कॉस्मिक ईवी में हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अनुभव में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मिशन उच्च प्रदर्शन वाले पर्यावरण के अनुकूल वाहन बनाना है जो आपकी अपेक्षाओं से बढ़कर हों। हम हर वाहन में सर्वोत्तम गुणवत्ता और प्रदर्शन देने का वादा करते हैं।''

इस नई साझेदारी पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सौरव गांगुली ने कहा, ₹राफ्ट कॉस्मिक ईवी का हरित भविष्य का दृष्टिकोण मुझे प्रभावित करता है। ये इलेक्ट्रिक वाहन अत्याधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।''

राफ्ट कॉस्मिक ईवी की स्थापना एक हरित और स्वस्थ भविष्य की दृष्टि से की गई थी। कंपनी ने उत्साही इंजीनियरों और डिजाइनरों की एक टीम के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की यात्रा शुरू की है।

सर्वे: दिल्ली की एयर क्वालिटी से असंतुष्ट हैं 86% लोग, 60% चाहते हैं कि ईवी से की जाए डोर स्टेप डिलीवरी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में सर्दियां खराब वायु गुणवत्ता के लिए कुख्यात हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन सोमवार 9 सितंबर को जारी एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 60.5% लोग लास्ट माइल डिलीवरी यानी डोर स्टेप डिलीवरी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के पक्ष में हैं। ताकि वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके।

लास्ट माइल डिलीवरी का मतलब किसी भी माल को वितरण केंद्र से ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाने से है। यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि साल 2024 तक, अंतिम मील डिलीवरी क्षेत्र पांच लाख टन सीओ2 यानी कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी करता है।

यह जानकारी विश्व ईवी दिवस के मौके पर 'सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी नेटवर्क' की ओर से 9 सितंबर को एक वेबिनार के दौरान जारी की गई। सर्वेक्षण का शीर्षक ₹अंतिम मील डिलीवरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के शामिल करने पर उपभोक्ता धारणाएं और अंतर्दृष्टि₹ था, जिसमें ईवी में संक्रमण के प्रति उपभोक्ताओं की राय और ब्रांडों के प्रति उनकी वरीयताओं का आकलन किया गया।

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि लगभग 70 फीसदी उपभोक्ता उन ब्रांडों की तरफ स्विच करने के लिए तैयार हैं, जो उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को कम करने की ठोस प्रतिबद्धताएँ रखते हैं। हालांकि, इस दिशा में अंतिम मील डिलीवरी कंपनियों की ओर से की जा रही कोशिशों की जानकारी बेहद कम है। सर्वे के अनुसार केवल 24.7% उपभोक्ताओं को इस विषय पर पर्याप्त जानकारी मिली है, जबकि 61% उपभोक्ता कंपनियों की ईवी ट्रांजिशन की प्रक्रिया से अनजान हैं।

सर्वेक्षण में शामिल 72.1% लोगों ने माना कि वे उन कंपनियों से खरीदारी करना पसंद करेंगे, जो अपने कर्मचारियों के लिए ईवी में ट्रांजिशन की दिशा में काम कर रही हैं। इसके साथ ही, 73% उपभोक्ताओं ने कहा कि डिलीवरी कंपनियों के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित ईवी ट्रांजिशन समय सीमा और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता चाहते हैं कि कंपनियां स्थिरता के लिए उठाए जाने वाले कदमों का खर्च खुद वहन करें, न कि उपभोक्ताओं पर इसका अतिरिक्त भार डालें।

इस सर्वेक्षण में 6 राज्यों और 10 प्रमुख शहरों के 3,800 उपभोक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, आसनसोल, कोयम्बटूर, चेन्नई, बैंगलोर, हुबली-धारवाड़ और अहमदाबाद के लोग शामिल थे।

'अंतिम मील डिलीवरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के ट्रांजिशन के लिए उपभोक्ता धारणा और अंतर्दृष्टि' शीर्षक से इस सर्वेक्षण को अंतिम मील डिलीवरी कंपनियों के बेड़े के ईवी में संक्रमण के चारों ओर प्रमुख संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। यह सर्वेक्षण अंतिम मील डिलीवरी के साथ जुड़े वायु प्रदूषण के प्रति जनता की धारणा और ब्रांडों द्वारा ईवी में संक्रमण की मांग के पैमाने को मापता है, जिनमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, नायका, अजियो, बिगबास्केट, जियो मार्ट, स्नैपडील, जेप्टो, डीएचएल/ब्लू डार्ट, स्विगी मार्ट, ग्रोफर्स/ब्लिंकिट, डीटीडीसी, टाटा क्लिक, डेल्हीवर, डुन्ज़ो, फेडेक्स शामिल हैं।

घरेलू बचत घटने की चिंताएं

डा. जयंती लाल भंडारी

विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय संगठनों की रिपोर्टों में भी इस बात का विश्लेषण किया जा रहा है कि लोगों को घरेलू बचत की योजनाओं तथा बैंकों में बचत की धनराशि जमा करने से मिलने वाले रिटर्न की तुलना में शेयर बाजार, म्यूच्युल फंड और अन्य भौतिक सम्पत्तियों में निवेश करने से अधिक रिटर्न मिल रहा है। अतएव घरेलू बचत में कमी आ रही है। यद्यपि घरेलू बचत के घटने की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू बचत का घटना किसी पारिवारिक या सामाजिक वित्तीय संकट की आहट नहीं है

यकीनन इस समय देश में आम आदमी का पहला आर्थिक और वित्तीय सहारा कही जाने वाली घरेलू बचत में लगातार कमी आने का चिंताजनक रुझान दिखाई दे रहा है। घटती हुई घरेलू बचत के खतरे को भांपते हुए हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में कहा कि बैंकों के द्वारा जमा राशि बढ़ाने के लिए ऐसी आकर्षक ब्याज योजना लाई जानी चाहिए, जिससे बैंकों में सेविंग्स की धनराशि में तेज इजाफा हो सके। गौरतलब है कि घरेलू बचत किसी व्यक्ति की आय की वह शेष राशि है, जो उपभोग आवश्यकताओं और विभिन्न वित्तीय देनदारियों के भुगतान के बाद बचती है। घरेलू बचत को बैंक और गैर बैंक जमा, जीवन बीमा निधि, भविष्यनिधि और पेंशननिधि, पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं तथा अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश किया जाता है। यदि हम घरेलू बचत संबंधी आंकड़ों को देखें तो पाते हैं कि जो घरेलू बचत वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 18 फीसदी के स्तर पर थी, वह वर्ष प्रतिवर्ष घटते हुए वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 5.2 फीसदी स्तर पर आ गई और अब यह पिछले पांच दशकों में सबसे कम स्तर पर है। स्थिति यह है कि घरेलू बचत में गिरावट सरकार की भी चिंता का कारण बन गई है। राष्ट्रीय लघु बचत प्राप्तियों के लिए इस वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में 14.77 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन 23 जुलाई को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में लघु बचतों से प्राप्ति के अनुमान को घटाकर 14.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। चूंकि सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए लघु बचत योजनाओं के तहत संग्रह राशि का भी उपयोग करती है।

निःसंदेह शताब्दियों से भारत एक ऐसा देश रहा है जहां लोग कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए घरेलू बचत के रूप में बचाकर रखते रहे हैं। लेकिन अब इस बचत की प्रवृत्ति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। लोगों के द्वारा आवास, वाहन, शिक्षा तथा अच्छे आरामदायक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के कर्ज लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जहां परिवारों की वित्तीय देनदारियां बढने से घरेलू बचत सीधे तौर पर कम हुई है, वहीं आय के एक हिस्से का इस्तेमाल विभिन्न

प्रकार के ऋणों के ब्याज के भुगतान के लिए भी किए जाने से घरेलू बचत कम हुई है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि देश में लघु बचत योजनाओं के तहत जो 40 करोड़ से अधिक बचतकर्ता हैं, उनके द्वारा भी विभिन्न लघु बचत योजनाओं में तुलनात्मक रूप से कम ब्याज मिलने के कारण निवेश में कमी आई है। प्रमुख रूप से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी) और सुकन्या समृद्धि खाता जैसी अन्य योजनाओं के तहत कम निवेश प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश में बदली हुई आयकर व्यवस्था के कारण भी आयकरदाताओं के द्वारा की जाने वाली घरेलू बचत में कमी आ रही है। इस समय देश में आयकर भुगतान की पुरानी और नई दो कर रिजीम हैं। जहां पुरानी कर रिजीम में बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहन हैं, वहीं नई कर रिजीम में बचत के वैसे प्रोत्साहन नहीं हैं। इस समय ज्यादातर आयकरदाता नई कर रिजीम अपना रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इस वर्ष 31 जुलाई तक आयकर आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई कर रिजीम के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी कर रिजीम में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है। इस प्रकार लगभग 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है। स्पष्ट है कि नई कर व्यवस्था से बचत व निवेश की जगह उपभोग खर्च बढ़ाने की प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

घरेलू बचत में कमी का एक कारण देश में महिलाओं के द्वारा उनके पास आने वाले धन का उपयुक्त निवेश नहीं किया जाना भी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक देश के बैंकों में कुल 252 करोड़ व्यक्तिगत खातों में से हर तीसरा खाता महिला के नाम पर है, लेकिन बैंकों में जमा कुल 187 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 20 फीसदी ही महिला खातों में जमा हैं। ऐसा नहीं है कि घरेलू बचत में कमी का कारण देश में लोगों की आय में कमी आना है। वस्तुतः भारत में प्रतिव्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही है। 10 वर्ष पहले वर्ष 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आय 86647 रुपए थी, वह 2023-24 में करीब 2.28 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह तेजी से बढ़ी आय के साथ अब बड़ी संख्या में लोग अपनी बचत का ऐसी जगह पर निवेश कर रहे हैं, जहां उनको ज्यादा ब्याज और ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। लोगों की बचत का तेज प्रवाह शेयर बाजार म्युचुअल फंड, रियल एस्टेट, महंगे वाहनों, सोने एवं बहुमूल्य धातुओं की खरीदी और आरामदायक व विलासिता के सामानों की ओर बढ़ रहा है। देश के छलांगे लगाकर बढ़ते हुए शेयर बाजार में भी तेज रिटर्न मिल रहा है। 10 वर्ष पहले जो सेंसेक्स 25 हजार के स्तर पर था, आज वह 80 हजार के ऊपर है। जुलाई 2024 में भारतीय शेयर बाजार का आकार 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है और भारत का शेयर बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। बड़ी संख्या में लोगों के कदम म्युच्यल फंड की ओर बढ़े हैं। जून 2024 तक म्युच्यल फंड के लिए डीमैट खातों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढक़र 16.2 करोड़ हो गई है।

विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय संगठनों की रिपोर्टों में भी इस बात का विश्लेषण किया जा रहा है कि लोगों को घरेलू बचत की योजनाओं तथा बैंकों में बचत की धनराशि जमा करने से मिलने वाले रिटर्न की तुलना में शेयर बाजार, म्यूच्युल फंड और अन्य भौतिक सम्पत्तियों में निवेश करने से अधिक रिटर्न मिल रहा है। अतएव घरेलू बचत में कमी आ रही है। यद्यपि घरेलू बचत के घटने की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू बचत का घटना किसी पारिवारिक या सामाजिक वित्तीय संकट की आहट नहीं है। रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में परिवारों की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि के बावजूद, परिवारों की बैलेंस शीट बेहतर बनी हुई है। मार्च 2023 के अंत में परिवारों की वित्तीय संपत्तियां उनकी देनदारियों की तुलना में 2.7 गुना थीं। भारतीय परिवारों का ऋण सेवा बोझ, यानी आय के प्रतिशत के रूप में ब्याज का भुगतान मार्च 2021 में 6.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2023 में 6.7 प्रतिशत रह गया, जो वैश्विक स्तर पर भी सराहनीय है। हम उम्मीद करें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को तत्परतापूर्वक घरेलू बचतों के निवेश को आकर्षक और जोखिम रहित बनाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके मद्देनजर सभी बैंक अपनी बचत योजनाओं को आकर्षक बनाएंगे।

ज्ञान

कांगड़ा का चमन

जब भी प्रदेश की सियासत का मुआयना होता है, कांगड़ा के मुद्दों पर सवार होना होता है। इस बार मौका भाजपा के हाथ आया तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा के सदन को तपा दिया। 'खामोशियां फिर तूफानों सी गूंज गईं, इस हवा को हमारे आंगन से कुछ कहना था।' जयराम बोल रहे थे तो कांगड़ा की चुप्पियों का पदचाप सदन के सन्नाटे तोड़ रहा था, लेकिन सियासत के खंभों पर कांगड़ा के ही नेता फिसले है। पौध बदल जाती है, कभी शांता-कभी धूमल में बंट जाती है। हकीकत यह भी है कि सत्ता का तिलक जब भी शिमला में सरकार के माथे पर लगा, तो कांगड़ा कश्तियों पर सवार रहा, लेकिन बार-बार इसी के 'पत्तन टूटे' हैं। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष ने कहा, वही कांगड़ा का अवतार है, लेकिन सच यह भी है कि कांगड़ा को मिलते रहे 'राजधानियों के दर्जों' ने इसी से वफा की। यह दीगर है कि कांगड़ा के प्रणेता के रूप में वीरभद्र की सत्ता के हर दशक ने इस क्षेत्र के मतदान का कर्ज उतारा है और अंतिम पैगाम आने तक शीतकालीन राजधानी का मील पत्थर धर्मशाला में सरकार को चुंबक बन कर खींचता रहा या तपोवन में शीतकालीन सत्र में तपते प्रश्न सुकून देते रहे। आश्चर्य यह कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की अस्थायी छत बनी, लेकिन जदरांगल परिसर पर कोई सरकार ईमानदार नहीं रही। धूमल की दौलत में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की गिरफ्त में आकर, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजनीति करने लगा। सांसद व मंत्री रहे अनुराग ठाकुर की विरासत में जब केंद्रीय विश्वविद्यालयय पलने लगा, तो जदरांगल परिसर की परीक्षाएं अब सुक्खू सरकार में अलग-अलग 'कांगड़ों' में दिखाई देने लगीं। मामला देहरा में उठती इमारतों में दब जाएगा या उपचुनाव की देहरी पर मुख्यमंत्री के वादे से जदरांगल परिसर बच जाएगा।

बेशक कांगड़ा पर्यटन की राजधानी बनने का हुनर जानता है, लेकिन एडीवी की योजनाओं में किसका जहर भरता है। प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन धर्मशाला की सियासी आबोहवा में उजड़ गया, तो वहां खर्च हुए सात करोड़ पर कौन रहम खाएगा। बीड़-बिलिंग में राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग स्कूल की बनी बनाई इमारत में कब कोर्स चलाया जाएगा। कभी धूमल ने धर्मशाला को खेल राजधानी कहा, लेकिन बजट के बावजूद साई के राष्ट्रीय खेल छात्रावास की योजना उजड़ गई। अब हाई अल्टीट्यूट खेल संस्थान के नाम 27 एकड़ जमीन किससे फरियाद करे। चैतड़ू का आई टी पार्क कहीं तो राजनीतिक गुनाहों का देवता बना। देश में प्रवासी पक्षी जिस पौंग झील को 'रामसर' का दर्जा दिला देते हैं, वहां विस्थापितों की चिंता की लकीरें पानी में लहर बन जाती हैं आज भी। बांटा तो कांगड़ा एयरपोर्ट भी बार-बार गया। शकुनि विरोध की तमस में वर्षों से जल रही परियोजना को छाती से लगा कर निश्चित रूप से सुखविंदर सुक्खू ने अपने सीने का फैलाव बताया है। कांगड़ा पर्यटन कैपिटल के कई दुर्ग नजर आ रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर्यटक गांव में चली जा रही होगी। धर्मशाला कानवेंशन सेंटर से जमीन छीनी जा रही होगी, लेकिन मानना पड़ेगा कि सुक्खू सरकार के इरादों ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार का पूरा नक्शा और खाका जमीन पर उतार दिया है। गनीमत होगी अगर कांगड़ा में पर्यटन राजधानी के असली मकसद को छीनने के लिए स्थानीय नेता अपने-अपने राजनीतिक दुर्ग के लिए परियोजनाओं को छीन कर बर्बाद न कर दें। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कांगड़ा पर्यटन राजधानी की संभावनाओं में सियासत अपनी संभावनाओं की खींचतान कर रही है।

हरित ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण एवं विकास

शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण से जुड़े विषय शामिल किए जाएं। ठोस और तरल अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रभावी नीति बनाई जाए। शहरों में कचरा प्रबंधन को पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाया जाए'

ऊर्जा और जीवन एक-दूसरे के पर्याय हैं। बिना ऊर्जा के विकास गतिविधियां संभव नहीं हैं। जीवाश्म ईंधन की वजह से पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु संकट का सामना करना पड़ रहा है। जीवाश्म ईंधन जलाने से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। पर्यावरण चुनौतियों से निपटने का एक ही विकल्प है हरित ऊर्जा। हरित ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा है। पर्यावरण संरक्षण, अच्छी प्राणवायु व स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के लिए हमें आज हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। हरित प्रौद्योगिकियां ऐसे उत्पाद और सुविधाएं बनाती हैं जो पर्यावरण मैत्री है तथा प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण एवं समाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। हरित प्रौद्योगिकियां नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पृथ्वी को बचाने का काम करती हैं। हरित ऊर्जा हमें सूर्य-प्रकाश, पवन, वर्षा, ज्वार, पौधों एवं भूतापीय गर्मी से प्राप्त होती है। पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता को बिना क्षति पहुंचाए राजस्व लाभ, रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार ने क्रांतिकारी एवं साहसिक कदम उठाते हुए 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य (ग्रीन एनर्जी स्टेट) विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस सकारात्मक सोच से जहां प्रदेश वासियों को स्वच्छ वायु, स्वास्थवर्धक वातावरण, रोजगार मिलेगा, वहीं प्रदेश को राजस्व लाभ एवं ऊर्जा संकट से निदान मिलेगा। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा, जल विद्युत और हाइड्रोजन का दोहन कर प्रदेश को सशक्त हरित ऊर्जा राज्य बनाने हेतु वचनबद्ध है। सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत है। एक घंटे की सूर्य रोशनी में दुनिया के लिए एक वर्ष की ऊर्जा समाहित है। सूर्य प्रकाश को फोटोवोल्टिक सेल से सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में मार्च 2024 तक 81.81 गीगावॉट सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता प्राप्त की है। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल की भागीदारी बढ़ाकर 12 प्रतिशत तक पहुंचाना चाहती है। प्रदेश भर में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ऊना जिले के पेखूबेला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की गई है तथा अघलौर में 10 मेगावाट और भंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हिमाचल प्रदेश गांव में बसता है तथा गांवों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए सौर ऊर्जा बेहतरीन विकल्प है। सौर लालटेन, सौर स्ट्रीट लाईट, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए माइक्रो-मिनी ग्रिड ने गांवों में नए उजाले की शुरुआत की है। अभी हाल ही में कुल्लू के मलाणा में बादल फटने से ऐसी आपदा बरसी कि पावर प्रोजैक्ट की डैम साइट बर्बाद हो गई। मलाणा के लोग अंधेरे में बस रहे हैं। ऐसे में मेक माई ट्रिप फाउंडेशन ने मलाणा को प्रकाशमय करने के लिए 500 सोलर लाइट्स प्रदान की हैं। प्रशासन द्वारा प्रति घर एक-एक सोलर लाइट दी जा रही है। सोलर लाइट सिस्टम से तीन बल्ब जलेंगे तथा फोन चार्ज करने की भी सुविधा है। राज्य की कुल चिन्हित जल विद्युत क्षमता लगभग 27 हजार 436 मेगावाट है। दोहन योग्य विद्युत क्षमता 23 हजार 750 मेगावाट है। वर्तमान में 10 हजार 781.88 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है।

हरित ऊर्जा के दोहन में ग्रीन हाइड्रोजन विशेष है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक कर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो बिजली प्राप्त होती है, उससे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। हरित हाइड्रोजन एक स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन है। हाइड्रोजन का हरित रूप पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन शून्य है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में आंचल इंडिया कंपनी के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए एक मेगावाट का संयंत्र उद्योग लगाया गया है, जो कि प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। प्रदेश में ग्रीन इलेक्ट्रिल व्हीकल पॉलिसी लागू की गई है। परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। बायो एनर्जी की क्षमता का दोहन करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने में इलेक्ट्रिक वाहन की अहम भूमिका है। पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10000 से अधिक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा चुके हैं। प्रदेश सरकार प्रदेश में प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों के लिए मुफ्त जमीन व बिजली उपलब्ध करवा रही है। गौरतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करते हैं जिससे प्रदेश के युवा, नौकरीपेशा व आमजन इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ई-वाहन ईंधन के रूप में प्रदान की गई बिजली का 62 प्रतिशत हिस्सा उपयोग में लाते हैं जबकि पेट्रोल संचालित वाहनों में पेट्रोल से सिर्फ 17 से 21 प्रतिशत ऊर्जा ही ईंधन में तब्दील होती है। प्रदेश को हरित राज्य बनाने हेतु राष्ट्रीय और राजमार्गों में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहे हैं। यह ग्रीन कॉरिडोर जहां एक ओर प्रदेश की खूबसूरती में इजाफा करेंगे, सफर को आनंदमय बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को आकर्षित कर राजस्व वृद्धि में सहायक होंगे। प्रदेश सरकार को चाहिए कि हरित व स्वच्छ हिमाचल के इस मिशन में नवाचार को सम्मिलित करें।

सोलन के वैज्ञानिकों ने क्लोरेला पाइरेनोइड़ोसा नाम के शैवाल का प्रयोग कर बायो वेस्ट से बायोडीजल बनाया है जो कि सस्ता एवं ईको फ्रेंडली है। एथेनॉल संचालित वाहनों में प्रदूषण शून्य रहता है। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण से जुड़े विषय शामिल किए जाएं। ठोस और तरल अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रभावी नीति बनाई जाए। शहरों में कचरा प्रबंधन को पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाया जाए। ईको टूरिज्म, जैविक खेती, पारिस्थितिकी, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए। सरकार, प्रशासन, स्थानीय समुदायों व सर्व सहयोग से प्रदेश के दो औद्योगिक शहरों परवाणू और काला अंब को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर हर प्रदेशवासी को साधुवाद। इस हरित आंदोलन में हर प्रदेशवासी, शैक्षणिक संस्थानों, यूथ क्लबों, महिला मंडलों, पंचायतों, उद्योगों को सहयोग देना चाहिए। अंत में हमें सीनेटर बॉब ब्राउन के कथन को याद रखना होगा, 'भविष्य या तो हरा-भरा

स्वास्थ्य सेवा में बदलाव के लिए शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता

विजय गर्ग

स्वास्थ्य सेवा में बदलाव के लिए शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है भले ही भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में खड़ा है, देश में कुशल, सक्षम स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। हालाँकि, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से गुणवत्ता और दक्षता से संबंधित कई चुनौतियों से जूझती है, जिससे बदलती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुसज्जित कार्यबल तैयार करने की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट व्यापक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करती है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें देश भर में मेडिकल कॉलेजों का असमान वितरण, जो कई छात्रों तक पहुंच में बाधा डालता है, यूजी और पीजी सीटों की कमी शामिल है। हालाँकि, चिकित्सा शिक्षा में बदलाव के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो केवल मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ाने से परे हो। गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को महत्वपूर्ण सोच कौशल और व्यावहारिक दक्षताएं मिलें जो आधुनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की नींव हैं। योग्यता आधारित शिक्षा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का गठन और सामान्य प्रवेश और निकास परीक्षाओं की शुरूआत चिकित्सा शिक्षा को मानकीकृत करने की दिशा में कदम हैं। हालाँकि, समय की मांग योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में व्यापक बदलाव और आधुनिकीकरण की है। यह वास्तविक दुनिया के स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्यों पर केंद्रित है और पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रटने की अपेक्षा व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर दिया जाता है। एनएमसी ने सीबीएमई विनियम, 2023 के साथ दिशानिर्देश सुझाए हैं। हालाँकि, अगर हमें भारत में सीबीएमई को सफलतापूर्वक लागू करना है तो हमें केवल दिशानिर्देश तैयार करने से आगे जाना होगा। हमें एक मजबूत आधार बनाने में निवेश करने की जरूरत है, जिसमें प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा और निरंतर मूल्यांकन शामिल है। हमें सीबीएमई शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित

शिक्षकों का एक समूह बनाने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करके संकाय विकास को भी मजबूत करना चाहिए। सीबीएमई को लागू करने की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, नियामक निकायों और चिकित्सा संस्थानों को शामिल करने वाला एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षा तक न्यायसंगत पहुंच शहरी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की सघनता ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। जिला अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की सरकार की पहल एक सकारात्मक कदम है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संस्थानों को पर्याप्त संसाधन मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अनुभवी संकाय हों, जो एक कठिन चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहित करना एक क्रांतिकारी कदम होगा। हालाँकि यह वित्तीय सहायता और करियर में उन्नति के अवसरों के रूप में हो सकता है, लेकिन रहने और काम करने की स्थिति में सुधार आवश्यक है। डॉक्टरों के पास अपने मरीजों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सही बुनियादी ढांचा होना चाहिए। भविष्य की आवश्यकताएँ भारत को विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए एक दूरदर्शी रणनीति की आवश्यकता है जो देश की बीमारी के बोझ और अनुमानित स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में देश भर के 6,064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक की कमी है। सुपर स्पेशलिस्ट की कमीविभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों में सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर। हालाँकि, विशेषज्ञता में बेतरतीब ढंग से सीटें बढ़ाने के बजाय, भविष्य की मांग के अनुमान के साथ-साथ अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करने के लिए महामारी विज्ञान के रुझान, जनसंख्या जनसांख्यिकी और तकनीकी प्रगति का विश्लेषण करने के लिए अस्पतालों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र), सरकारी एजेंसियों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय?

परिवहन विशेष न्यूज

बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इसे 11 सितंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। इस आईपीओ से कंपनी का 6560 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये तय किया है। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ को ग्रे मार्केट (बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जीएमपी आज) में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?

नई दिल्ली। बजाज ग्रुप की बजाज हाउसिंग फाइनेंस (Bajaj Housing Finance IPO) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज (9 सितंबर) को खुल गया। इसे 11 सितंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। बजाज इस आईपीओ से 6,560 करोड़ रुपये जुटाने वाली है। वह 104 एंकर निवेशकों से 1,758 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। इनमें मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन्हें 70 रुपये के भाव पर 25.11 करोड़ शेयर जारी हुए हैं।

Bajaj Housing Finance IPO का लेखाजोखा

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को 9 से 11 सितंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। इसका प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये है। वहीं, लॉट साइज 214 शेयरों का है। इसका मतलब कि आपको अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट के लिए कम से कम 14,980 रुपये निवेश करना होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 12 सितंबर को होगा और इसकी स्टॉक मार्केट में एंट्री 16 सितंबर को होगी।

इस आईपीओ के तहत 3,560.00 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे। वहीं, 42,85,71,429 शेयरों की ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बिक्री होगी। इसमें इसकी पैरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) शेयर बेचेगी। ऑफर फॉर सेल का पैसा स्टॉक बेचने वाले शेयरहोल्डर्स को मिलेगा। वहीं नए शेयरों के पैसों का इस्तेमाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कैपिटल बेस को बढ़ाने में होगा।

Bajaj Housing Finance IPO GMP today

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) 56.70 रुपये है यानी आईपीओ निवेशकों को 81 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसकी लिस्टिंग 120 रुपये से अधिक पर हो सकती है। ग्रे मार्केट एक अन-ऑफिशियल बाजार है, जहां आईपीओ की लिस्टिंग से पहले उसकी डिमांड का अंदाजा मिलता है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि निवेशकों को ग्रे मार्केट के बजाय कंपनी के फंडामेंटल और वित्तीय सेहत के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना चाहिए।

Bajaj आईपीओ पर एक्सपर्ट की क्या राय है?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर ज्यादा ब्रोकरेज का सकारात्मक रुझान है। उनका कहना है कि कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है। इसकी सेल्स और प्रॉफिट में लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी वित्तीय सेहत भी काफी मजबूत है। इसके सिर पर बजाज जैसे विशाल ग्रुप का हाथ है। वैल्यूएशन के मोर्चे पर एक्सपर्ट की थोड़ी बंटी हुई है। कुछ प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले इसका वैल्यूएशन अधिक है। लेकिन, अधिकांश इसके वैल्यूएशन को एकदम सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस आईपीओ को न सिर्फ लिस्टिंग गेन, बल्कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी सब्सक्राइब किया जा सकता है।

Bajaj Housing Finance क्या करती है?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस की नींव 2008 में पड़ी। बजाज ग्रुप की यह कंपनी साल 2018 से घर बनवाने के लिए कर्ज दे रही है। कंपनी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स को घर और कमर्शियल स्पेस खरीदने में कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन उपलब्ध करवाती है। बजाज ग्रुप व्हीकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। Bajaj Housing Finance के पास 308,693 एक्टिव कस्टमर हैं। इनमें से 81.7 प्रतिशत ने कंपनी से होम लोन लिया है। कंपनी की देशभर में 215 ब्रांच हैं।

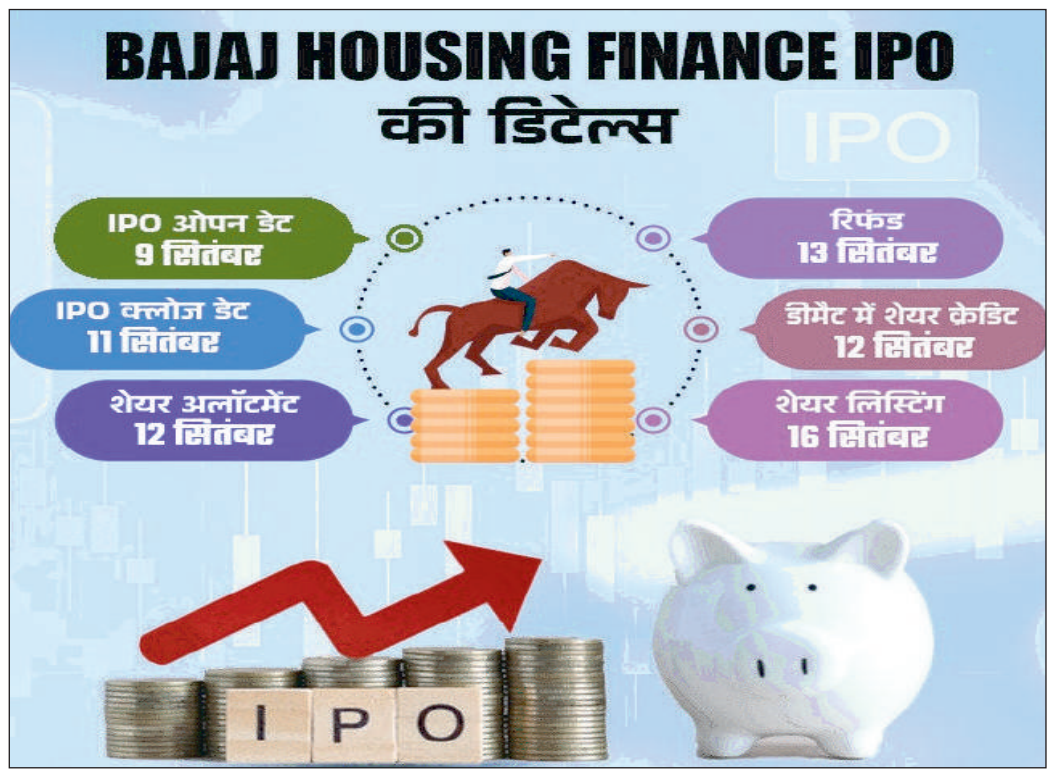

एलन मस्क, गौतम अदाणी या मुकेश अंबानी... कौन बनेगा दुनिया का पहला खरबपति?

परिवहन विशेष न्यूज

इंफॉर्मा कनेक्ट एकेडमी की 2024 ट्रिलियन डॉलर क्लब रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर एलन मस्क (Elon Musk) होंगे जो टेस्ला (Tesla) स्पेसएक्स (SpaceX) जैसी कंपनियों के साथ-साथ X के मालिक हैं। अगले तीन साल में उनकी नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है। मस्क के बाद गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी जैसे भारतीय कारोबारी भी इस क्लब का हिस्सा बन सकते हैं।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के करिश्माई सीईओ एलन मस्क 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति (कम से कम एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की कुल संपत्ति) बन सकते हैं। भारतीय कारोबारी भी ज्यादा पीछे नहीं रहने वाले नहीं। अदाणी ग्रुप के मालिक गौतम अदाणी 2028 और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी 2033 तक खरबपतियों की लिस्ट में शुमार हो सकते हैं। यह जानकारी इंफॉर्मा कनेक्ट अकादमी की रिपोर्ट मिली है।

एलन मस्क कैसे बनेंगे पहले खरबपति?

एलन मस्क फिलहाल 237 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं। अगर उन्हें 2027 तक दुनिया का पहला खरबपति (Trillionaire) बनना है, तो उनकी संपत्ति में सालाना 110 फीसदी का इजाफा होने की जरूरत रहेगी। गौतम अदाणी अभी 100 अरब डॉलर से कम की संपत्ति के साथ विश्व अरबपति सूचकांक में 13वें स्थान पर हैं। अगर उनका बंदरगाहों से लेकर बिजली तक फैला साम्राज्य मौजूदा 123 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ना जारी रखता है, तो वह शायद दुनिया के दूसरे खरबपति बन सकते हैं।

मुकेश अंबानी बनेंगे तीसरे खरबपति

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी 111 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ अब एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। हालांकि, वह ट्रिलियनेयर का दर्जा 2033 में हासिल कर सकते हैं। उनका तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र का समूह 2035 में ट्रिलियन-डॉलर मार्केट कैप की स्थिति तक पहुंचने वाला है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकलौती भारतीय कंपनी है, जो उस मुकाम तक पहुंच सकती है।

ट्रिलियन-डॉलर मार्केट कैप के निशान को छूने वाली कंपनियों में ताइवान की सेमीकंडक्टर निर्माता TSMC शामिल है। उसका मार्केट कैप अभी 893.7 बिलियन डॉलर है। वह अगले साल तक यह रुतबा हासिल कर सकती है। इसके बाद फार्मा दिग्गज एली लिली, ब्रॉडकॉम और टेस्ला का स्थान होगा।

अभी तक कोई भी ट्रिलियनेयर नहीं

इंफॉर्मा कनेक्ट अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक, ₹अभी तक दुनिया में किसी भी कारोबारी ने ट्रिलियनेयर का दर्जा हासिल करने का दावा नहीं किया है। हालांकि, कुछ संभावित मल्टी-बिलियनेयर उम्मीदवार हैं, जो शायद जल्द या कुछ समय बाद ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। एलन मस्क और गौतम अदाणी के बाद NVIDIA के फाउंडर जेन्सेन हुआंग, इंडोनेशियाई कारोबारी प्राजोगो पंगेस्टु, फ्रांसीसी व्यवसायी बर्नार्ड अर्नाल्ट और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग संभावित खरबपतियों की लिस्ट में शुमार हैं।

अभी चंद कंपनियां ही हैं, जिन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यूएशन पार कर लिया है। इनमें Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Saudi Aramco और Meta शामिल हैं। सबसे हालिया मामला अगस्त के अंत में वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे का है। Nvidia भी मई 2023 में 1 ट्रिलियन डॉलर के क्लब में शामिल हो गई। इसका वैल्यूएशन जून में 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे यह दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। इसमें Microsoft उससे आगे और Apple पीछे है।

सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानिए क्या है लेटेस्ट प्राइस

घरेलू स्तर पर व्यापारियों ने सोने की कीमतों में गिरावट का कारण विदेशों में कमजोर रुख के बीच स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की सुस्त मांग को बताया। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोना 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2522.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। सोने का आगे भाव कैसा रहेगा यह काफी हद तक अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों में कटौती के फैसले पर निर्भर करेगा।

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपये टूटकर 73,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। शुक्रवार को पीली धातु 74,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की कमजोर मांग के कारण सोमवार को सोने की तरह चांदी की कीमत भी 2,000 रुपये टूटकर 83,800 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में चांदी 85,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

घरेलू स्तर पर व्यापारियों ने पीली धातु की कीमतों में गिरावट का कारण विदेशों में कमजोर रुख के बीच स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की सुस्त मांग को बताया। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोना 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,522.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटी) सौमिल गांधी ने कहा, "अमेरिकी रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कमतर रहे। इससे अनिश्चितता बढ़ गई कि आगामी मीटिंग में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कितनी कटौती करेगा। इसके चलते सोमवार को सोने के भाव में गिरावट आई।"

फेस्टिव सीजन में हवाई सफर महंगा होने पर केंद्र ने जताई चिंता, क्या यात्रियों को मिलेगी राहत?

फेस्टिव सीजन में बहुत से लोग अपने घर जाना चाहते हैं ताकि परिवार के साथ त्योहार मना सके। इस दौरान ट्रेन के साथ एयरलाइंस के टिकटों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। चूंकि ट्रेनें सरकार चलाती है तो उनके किराये में डिमांड के हिसाब से इजाफा नहीं होता। लेकिन विमानन कंपनियां डिमांड बढ़ने के साथ हवाई सफर महंगा कर देती हैं। ऐसे में सरकार को दखल देना पड़ा है।

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के दौरान विमानन कंपनियां अक्सर टिकट महंगा कर देती हैं। चूंकि, फेस्टिव सीजन में बहुत से लोग घर जाना चाहते हैं, ऐसे में टिकटों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इसका फायदा उठाने के लिए एयरलाइंस हवाई किराये का दाम बढ़ा देती हैं।

ट्रैवल पोर्टल इक्सिगो के एक एनालिसिस के मुताबिक, विमानन कंपनियां कई बिजी रूट पर किराया 20 से 25 फीसदी तक बढ़ा भी चुकी हैं। हालांकि, अब हवाई किराये में अधिक इजाफा होने के आसार नहीं हैं। दरअसल, सरकार कहना है कि वह 'स्थिति पर नजर' रखे हुए है, ताकि कंपनियां मनमाना किराया न वसूल सकें।

फेस्टिव में महंगा हो जाता है हवाई किराया

छुट्टियों के मौसम में हवाई टिकट की मांग अक्सर बढ़ जाती है। इससे टिकट प्राइस में भी बड़ा उछाल देखने को मिलता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पर बात करते हुए कहा, "हमारा मंत्रालय पहले से ही देश के उन सभी मार्गों की टिकट दरों पर नजर रख रहा है, जहां फेस्टिव सीजन के दौरान अधिक तादाद में लोग सफर करते हैं। हम किसी भी एयरलाइन को टिकट की वही कीमत रखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन, हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई विमानन कंपनी मनमाना किराया न वसूल पाए।"

फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी का बना रहे प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

परिवहन विशेष न्यूज

क्रेडिट कार्ड आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हम शॉपिंग से लेकर जरूरी बिल पेमेंट तक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान भी लोग बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग के करते हैं। कई ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑप्शन देते हैं। लेकिन फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नई दिल्ली। बहुत से लोग स्मार्टफोन या फिर टीवी-फ्रिज जैसे जरूरी घरेलू उपकरण खरीदने के लिए फेस्टिव सीजन का इंतजार करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, फेस्टिव सीजन के दौरान मिलने वाली भारी छूट। इस दौरान शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है।

क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर कई ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म अलग से डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। लेकिन, फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, नहीं तो आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं।

री-पेमेंट साइकल का जरूर ध्यान रखें

अगर आप फेस्टिव सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड से भारी-भरकम खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको री-पेमेंट साइकल का अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप EMI का समय पर पेमेंट नहीं करते, तो आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इससे बैंक आपको हाई रिस्क वाले कस्टमर की कैटेगरी में डाल सकता है। इससे आपको भविष्य में कर्ज लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि आप उतनी ही खरीदारी करें, जितना EMI आसानी से चुका जा सकें।

बकाया समय पर न चुकाने के नुकसान

अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान नहीं करते, तो बैंक आपसे बकाया रकम पर काफी ज्यादा ब्याज वसूलेगा। आप अधिक इंटरेस्ट रेट के चलते कर्ज के जाल में फंसते जाएंगे। इसका बुरा असर आपकी दूसरी योजनाओं, जैसे कि निवेश या बचत पर पड़ सकता है। आपको घर के जरूरी खर्चों में भी कटौती करनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको कुछ भी करके क्रेडिट कार्ड के बिल को तय समय पर चुका देना चाहिए।

सिर्फ डिस्काउंट के लिए न करें खरीदारी

फेस्टिव सीजन के दौरान कई ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म काफी तगड़ा डिस्काउंट देते हैं। ऐसे में कई लोग सिर्फ डिस्काउंट के लालच में खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन, ऐसा करने से बचना चाहिए। आपको वही चीजें खरीदनी चाहिए, जिसकी असल में आपको जरूरत है। जैसा कि अगर आपका पुराना टीवी या फ्रिज अच्छा काम कर रहा है, तो आपको सिर्फ इसलिए नया नहीं खरीद लेना चाहिए कि उस पर काफी शानदार डिस्काउंट मिल रहा है।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गिरावट के बाद दमदार रिकवरी, किस वजह से चढ़ा स्टॉक?

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर की कीमत ओला इलेक्ट्रिक के शेयर फ्लैट लिस्टिंग के बाद तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे थे। उन्होंने 150 रुपये से अधिक पर अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया। लेकिन वहां से इसने रिवर्स गियर लगा दिया है। इससे उन निवेशकों को काफी नुकसान हो रहा जिन्होंने इसे हाई पर खरीदा था। आइए जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गिरावट की क्या वजह क्या है?

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। भाविश अग्रवाल के मालिकाना हक वाली कंपनी के शेयर सोमवार (9 सितंबर) को शुरुआती कारोबार में ही 5 फीसदी से अधिक गिर गए। उसके करीब 18.18 करोड़ शेयरों का लॉक-इन पीरियड भी आज खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब इन शेयरों को बेचने पर लगी बंदिश हट गई। इससे निवेशक चाहें, तो वे इन शेयरों को बेचकर कंपनी से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि, ऐसा करना जरूरी नहीं है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक- 5 सितंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच ओला इलेक्ट्रिक समेत कुल 38 कंपनियों के करीब 21 अरब डॉलर के शेयरों का लॉक-इन पीरियड खत्म होगा। हालांकि, ब्रोकरेज ने यह भी स्पष्ट किया कि इन सभी शेयरों की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि इनका बड़ा हिस्सा प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास भी है।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर दोपहर 1 बजे तक 5.10 फीसदी की गिरावट के साथ 103.98 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। हालांकि, उसके बाद शेयरों में तेज रिकवरी दिखी और यह 4.13 फीसदी उछाल के साथ 114.10 रुपये पर बंद हुआ।

ओला इलेक्ट्रिक पर ब्रोकरेज का रुख

ब्रोकरेज फर्म HSBC ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों को 140 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवर कर रही है। उसका भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर काफी रूढ़िवादी नजरिया है। लेकिन, ब्रोकरेज को लगता है कि भारत सरकार पॉलिसी के मोर्चे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लगातार सपोर्ट दे रही है। वहीं, ओला के पास बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियत है, जिसकी बदौलत वह लागत कम कर सकती है। यही वजह है कि HSBC ने ओला को निवेश के लायक बताया है।

Ola Electric के शेयर में गिरावट क्यों?

ओला इलेक्ट्रिक के घाटे में लगातार वृद्धि हो रही है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट ओला के आईपीओ को काफी महंगा बता रहे थे। साथ ही, ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में भी गिरावट आई थी। यह जून तिमाही में 49 फीसदी थी, जो अगस्त के आखिर में घटकर 31 फीसदी रह गई। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक की टीवीएस और बजाज ऑटो जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। इससे ओला के निवेशकों की चिंता भी बढ़ रही है और वे बिकवाली करके इससे बाहर निकल रहे हैं।

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कब घटेगी GST, क्या है सरकार का इरादा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य मंत्रियों की मौजूदगी वाली जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक दिल्ली में हो रही है। इस मीटिंग में अधिकांश राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के हक में दिखे। दरअसल मासिक जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है।

नई दिल्ली। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर घट हो सकती है। अभी इन प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगती है। लेकिन, GST काउंसिल इस दर को कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बारे में आखिरी फैसला अगली मीटिंग में लिया जाएगा।

केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों की समिति (फिटमेंट कमेटी) ने सोमवार को जीएसटी काउंसिल के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें लाइफ, हेल्थ और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कटौती के आंकड़े और विश्लेषण दिए गए हैं। यह कमेटी टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए जरूरी सुझाव देती है।

ज्यादातर राज्य टैक्स कटौती के हक में

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य मंत्रियों की मौजूदगी वाली जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक दिल्ली में हो रही है। यह जीएसटी से जुड़े मामलों में फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। इस मीटिंग में अधिकांश राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के हक में दिखे। दरअसल, मासिक जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कमेटी को लगता है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के उपाय किए जा सकते हैं।

अगर जीएसटी रेट कम किया जाता है, तो करोड़ों पॉलिसीधारकों को फायदा होगा, क्योंकि प्रीमियम राशि घट जाएगी। जीएसटी से पहले बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगता था। 2017 में जीएसटी लागू होने पर सर्विस टैक्स को जीएसटी में शामिल कर लिया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों ने हेल्थ बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 8,262.94 करोड़ रुपये जुटाए। वहीं, हेल्थ री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 1,484.36 करोड़ रुपये वसूले गए।

100 साल पहले भी गणपति उत्सव में हिन्दुओं की एकता को देख बुरी तरह घबरा गए थे अंग्रेज : राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। गणेश चतुर्थी सम्पूर्ण हिंदू धर्म के लिए एक अति महत्वपूर्ण त्योहार है। आज़ देश गणेशोत्सव की भक्ति में लीन है। गणेश चतुर्थी का यह त्यौहार पूरे भारत में बड़े हर्ष और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा हैं। भक्त घरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणपति की मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित कर रहें हैं। 10 दिवसीय विशाल उत्सव नदियों या झीलों में मूर्तियों के विसर्जन के साथ समाप्त होता है, जो भगवान गणेश की कैलाश पर्वत पर वापसी का भी प्रतीक है।

गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना ने कहा, ॐ गं गणपतये नमः बुद्धि एवं समृद्धि के आराध्य देव भगवान श्री गणेश की कृपा हो और आपके जीवन में सदैव उत्साह, आनंद, उल्लास का वास हो। हर घर-आंगन में शुभता और मांगल्य की वर्षा हो, यही प्रार्थना है। गणेश जी आपको शक्ति प्रदान करें, आपके दुखों का नाश करें और आपके जीवन में खुशियां बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी आपको सुख, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें और श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। समस्त देशवासियों को पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

श्री खुराना ने आगे कहा, हमारा भारत देश अपनी सांस्कृतिक विशेषता के कारण दुनियां में एक अलग पहचान रखता है। यही सांस्कृतिक विशेषता हमारे देश को श्रेष्ठता प्रदान करती हैं, इस विशेषता के दर्शन तीज त्यौहार, उत्सव, परंपराओं में होते है। इसी तरह की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता भारत में दस दिवसीय गणेश उत्सव में नज़र आती हैं। इसीलिए यह उत्सव किसी विशेष जाति, वर्ग का नहीं होकर राष्ट्रीय उत्सव नजर आता है। गणेश उत्सव ने देश की राष्ट्रीय चेतना जगाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने कहा, देश की आजादी के आन्दोलन में गणेश उत्सव ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। गणेश चतुर्थी का योहार भारत में सदियों से पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा था, लेकिन सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने की परंपरा 100 साल पुरानी है। सबसे पहले राजा के महल में गणेशोत्सव होता था। उसके बाद राजबाड़े गणपति उत्सव मनाते थे। लेकिन बीएनसी मिल के ग़रीब मजदूर आंदोलन से राजनांदगांव में भी आजादी की लड़ाई का शंखनाद हो चुका था। इस आंदोलन से शहर के श्रमिक लोग जुड़ चुके थे। इसलिए पहली बार महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलकजी ने गणपति उत्सव की स्थापना की और सबसे पहले पुणे के शनिवारवाड़ा में गणपति उत्सव का आयोजन किया इस उत्सव में हजारों ग़रीब मजदूरों एवं लोगों की उमड़ी भीड़ ने हिन्दू एकता का रंग देने का कार्य किया और तिलकजी ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। इससे पूर्व गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा। बल्कि आजादी की लड़ाई, तात्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत भेदभाव को दूर करने और जाति, वर्ग, अमीर, गरीब के भेद से ऊपर उठकर समाज को एक रुपता प्रदान करने के लिए इससे बढ़कर उसे अंग्रेजो के खिलाफ एक आंदोलन का स्वरूप दिया। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेशउत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया वह समय के साथ बढ़ता चला गया। तिलक जी ने जिस हिन्दू एकता और सामाजिक समरसता के स्थापन के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाए जाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया था। इस उत्सव ने अंग्रेजों से आजादी के दौरान तो भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया जिससे यह श्रर्मिक आयोजन देशभक्ति, हिन्दू एकता और सामाजिक एकता का माध्यम बन गया। इस प्रकार, गणेश उत्सव की सार्वजनिक शुरूआत से सभी हिन्दुओं में सांस्कृतिक जागरूकता आई, बल्कि यह देशभक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गया। अंग्रेजो के विरुद्ध आजादी की लड़ाई में गणेश उत्सव से निर्मित सामाजिक एकता और हिन्दू एकता हथियार के रूप में सामने आने लगी और गणपति उत्सव में सभी हिन्दुओं की एकता को देख अग्रेज बुरी तरह घबरा गए थे। तिलक जी ने गणेश उत्सव को राष्ट्रीय हिन्दू एकता एवं सामाजिक समरसता का रूप दिया। उसके बाद महाराष्ट्र से यह उत्सव सम्पूर्ण भारत और दुनियां में मनाया जाने लगा। इस उत्सव की खास बात यह है की यह समाज के सभी वर्गों में समान उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छुआछूत भेदभाव और आर्थिक मतभिन्नता के परे इस उत्सव में गजब की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता के दर्शन होते है। आजाद भारत में भी गणेश उत्सव हिन्दू एकता, सामाजिक समरसता का प्रतीक बना हुआ है। गणेश उत्सव सांस्कृतिक रूप से भारतीय जनमानस में हिन्दू एकता स्थापित करने का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है।

उन्होंने आगे कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने का उद्देश्य सभी ग़रीब अमीर हिन्दुओं को एकजुट करना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्हें प्रेरित करना था। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक जी का मानना था कि जब भी देश के हिन्दुओं पर कोई बाहरी संकट आएगा तो सिर्फ़ हिन्दू ही हिन्दू को बचाएंगे। इसलिए सभी हिन्दूओं में एकता होना बहुत ज़रूरी हैं। इस बात को तब पहली बार सभी हिन्दुओं ने बहुत गंभीरता से समझा और गणपति उत्सव में अमीर ग़रीब की दूरी समाप्त कर सभी हिन्दूओं उत्साह के साथ मिलकर यह त्यौहार मनाया। इससे सभी हिन्दुओं में जागरूकता आयी और इस त्यौहार ने सभी हिन्दुओं को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जिससे यह श्रर्मिक आयोजन देशभक्ति, हिन्दू एकता और सामाजिक एकता का माध्यम बन गया। जिस उद्देश्य को लेकर तिलक जी ने गणेश उत्सव को प्रारम्भ करवाया था वो उद्देश्य आज कितने सार्थक हो रहें हैं। गणपति उत्सव में हर वर्ष हिन्दू एकत्रित होते हैं और राष्ट्रीयता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस तरह लोगों का गणपति उत्सव के प्रति उत्साह बढ़ता गया और राष्ट्र के प्रति चेतना बढ़ती गई। तो आइएं इस बार हम सभी ग़रीब अमीर हिन्दू एक बार फिर से संगठित होकर गणेशोत्सव को इतनी ख़ुशी उत्साह और धूमधाम से मनाएं, जिससे हिन्दू समाज में सभी ग़रीब अमीर हिन्दूओं में एकता और हिन्दू भाईचारा बढ़ सके। क्योकि गणेश उत्सव के दौरान बने रिश्ते हिन्दू समाज को आपस में जोड़ने का काम करते है। हिन्दू एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता की स्थापना में सहायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन आजकल कुछ हिन्दुविरोधी ताकतें हिन्दुओं को कभी जाति के नाम पर कभी आरक्षण के नाम पर कभी संबिधान के नाम पर गुमराह करके हिन्दू एकता को तोड़ने की नयी नयी गंदी साजिश रच रही हैं। इसलिए, राष्ट्रहित और हिन्दुहित में उन सभी हिन्दू एकता विरोधियों एवं देश के छिपे दुश्मनों से सावधान और सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। क्योकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है, जब सभी ग़रीब अमीर हिन्दू एकजुट होकर रहेंगे और हिन्दू समाज को बांटने वाली देश विरोधी ताकतों से सावधान रहकर इनका बहिष्कार करेंगे तभी सही मायने में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सेनानियों की पूजा सार्थक होगी।

उम्र 16 + 44 अनुभव = 60 वर्ष का

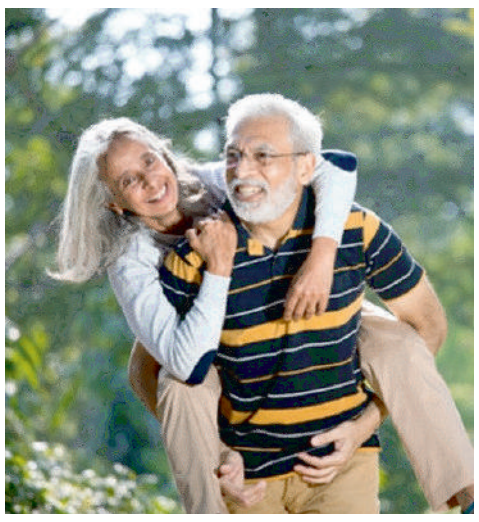

भाग्यशाली
बुजुर्ग नहीं
भाग्यशाली लोग

वे भाग्यशाली लोग हैं जो 60 पार कर गये। एक जापानी पुस्तक के अनुसार जापान में, डॉ वाडा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को, 'बुजुर्ग' कहने के बजाय, 'भाग्यशाली लोग' कहने की वकालत करते हैं।

डॉ. वाडा ने 60 साल के लोगों के
"भाग्यशाली व्यक्ति"
बनने के रहस्य को
"36 वाक्यों" में
इस प्रकार समझाया :-

1. चलते रहो।
2. जब आप चिड़चिड़ा महसूस करें तो गहरी सांस लें।
3. व्यायाम करें, ताकि शरीर में अकड़न महसूस न हो।
4. गर्मियों में, एयर- कंडीशनर चालू होने पर, अधिक पानी पिएं।
5. आप जितना चबाएंगे, आपका शरीर और मस्तिष्क उतना ही ऊर्जावान होगा।
6. याददाश्त उम्र के कारण नहीं, बल्कि लंबे समय तक मस्तिष्क का उपयोग न करने के कारण कम होती है।
7. ज्यादा दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है।
8. रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को जानबूझ कर कम करने की आवश्यकता नहीं है।
9. केवल वही काम करें, जिससे आप प्यार करते हैं।
10. चाहे कुछ भी हो जाए, हर समय घर में नहीं रहना चाहिए। रोज घर से बाहर जरूर निकलें, और टहलें भी।
11. जो चाहो खाओ, पर नियन्त्रित रखिये।
12. हर काम सावधानी से करें।
13. उन लोगों से वह व्यवहार न करें, जिससे आप भी नापसंद करते हैं।
14. अपनों का ख्याल रखें।
15. बीमारी से, अंत तक लड़ने के बजाय इसके साथ जीना बेहतर है।
16. मुश्किल समय में, आगे बढ़ने से मदद मिलती है।
17. हर बार, खाना खाने के बाद, थोड़ा सा गुनगुना पानी, अवश्य पियें।
18. रात में, जब भी उठें, पानी अवश्य पियें।
19. जब नींद नहीं आये, तो जबरदस्ती न करें।
20. खुशमिजाज चीजें करना, दिमाग को तेज करने वाली सबसे अच्छी गतिविधि है
21. अपने लोगों से बातचीत करते रहें।
22. एक ₹पारिवारिक चिकित्सक₹ को, अपने आसपास जल्दी खोज लें।
23. धैर्य रखें, लेकिन अत्यधिक नहीं, या हर समय अपने आप को अच्छा बनने के लिए मजबूर न करें।
24. नया सीखते रहें, वरना बूढ़े कहलाएंगे।
25. लालची मत बनो, अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वही अच्छा व काफी है
27. जब कभी बिस्तर से उठना हो, तो तुरंत खड़े न हों, 2-3 मिनट रुककर, उठें।
28. जितनी अधिक परेशानी वाली चीजें हैं, उतनी ही दिलचस्प हैं।
29. स्नान करने के बाद कपड़े पहनते वक्त दीवार आदि का सहारा लें।
30. वही करें, जो अपने और दूसरों के लिए हितकारी हो।
31. अपने आज को, इत्मिनान से जिएं।
32. इच्छा, दीर्घायु का स्रोत है!
33. एक आशावादी के रूप में जियें।
34. प्रसन्नचित्त व्यक्ति, लोकप्रिय होंगे।
35. जीवन और जीवन के नियम आपके अपने हाथों में हैं।
36. इस उम्र में सब कुछ शांति से स्वीकार करे!

सभी 60 पार कर चुके मित्रों को समर्पित।

हँसते रहिये हंसाते रहिये, तंदरुस्त रहिए

यू.पी. मोटर ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन की ओर से हाथरस एक्सीडेंट हादसे के मृतको को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। यू.पी. मोटर ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन की ओर से संवेदना जताते हुए एक ही परिवार के 21 लोगों की हाथरस में लोडर टैम्पू व बस एक्सीडेंट हादसे के मृतको को शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गयी।

हाथरस में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार शाम लोडर मैक्स वाहन और बस हादसे में एक ही परिवार के 21 लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आगरा के द्वारा शहीद स्मारक पर कैंडल जला मृतकों की आत्म की शांति के लिए प्रार्थना की गयी। संगठन के पदाधिकारीयो ने कहा, भविष्य में लोडिंग वाहनों में सवारियां ना बैठाई जाए इसे लेकर भी वह प्रयास करेंगे।

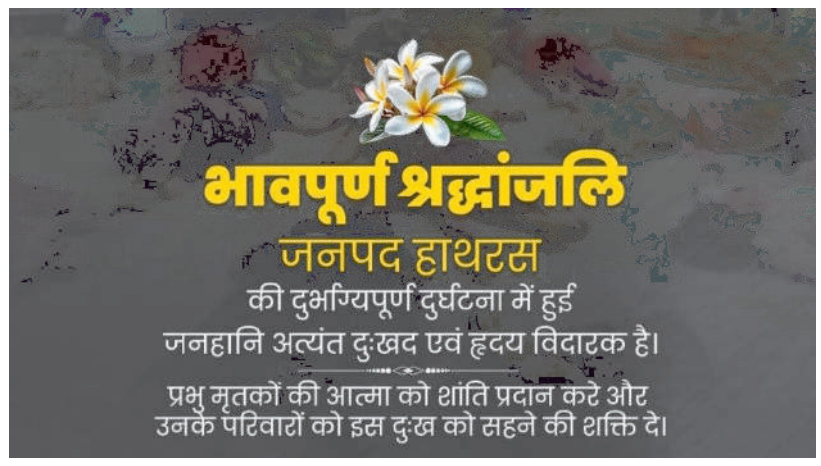

हाथरस में हुई हृदय विदारक घटना में दिवंगत हुए एक ही परिवार के 21 मृतकों की आत्म की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, उसके तत्पश्चात यू.पी. मोटर ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, हाथरस में एक ही परिवार के 21 लोगों की मृत्यु बेहद हृदयविदारक एवं काफ़ी दुःखद है। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं व्यथित कर देने वाली है। हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और परमात्मा से 10 से अधिक घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इस दुखद हादसे में जिन्होंने अपनों को खो दिया उन सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें एवं उनके सभी परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और साहस दें। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और सभी परिजनों को इस अपार कष्ट को सहन करने की शक्ति दे !! ॐ शांति !!

इस दौरान मुकेश माता, संजीव चौहान, भूपेंद्र राजावत, गोलू रावत, परमानन्द, गौरव चौहान, विजय सिकरवार, प्रेमचंद्र अग्रवाल, चेतन चौहान, सोनू शर्मा, रोहित रावत आदि उपस्थित रहें।

मालकानगिरि में भारी बारिश।बारिश का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 326 के पंगम पोल से दो फीट ऊपर बह रहा है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर् : मालकानगिरि में भारी बारिश। जहां विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं बारिश का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 326 के पंगम पोल से दो फीट ऊपर बह रहा है । मालकांगरी से संपर्क टूट गया है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से यातायात रोक दिया है। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां रुकी हुई हैं।इसी तरह मलकानगिरी जिले के पोटेरू में भी बाढ़ आई है। पोटेरू नदी की बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। लोगों के घर और सुपरमार्केट बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जैसे-जैसे बारिश जारी रहेगी स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है। लोगों ने अपना घर छोड़कर पोटेरू पुलिस स्टेशन की दो मंजिलों पर शरण ली।

डिफेंस क्षेत्र में मेड इन इंडिया को बड़ा बूस्टर, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ सुखोई के इंजन के लिए किया बड़ा करार

परिवहन विशेष न्यूज

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ देश ने एक और कदम बढ़ाया। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को लड़ाकू विमान सुखोई-30एमकेआइ के 240 एयरो-इंजन की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 26000 करोड़ रुपये का समझौता किया। एयरो-इंजन का निर्माण एचएएल के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा। इससे वायु सेना को सुखोई-30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली : रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ देश ने एक और कदम बढ़ाया। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को लड़ाकू विमान सुखोई-30एमकेआइ के 240 एयरो-इंजन की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 26,000 करोड़ रुपये का समझौता किया। एयरो-इंजन का निर्माण एचएएल के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा। इससे वायु सेना को सुखोई-30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में मंत्रालय और एचएएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के तहत एचएएल प्रति वर्ष 30 एयरो इंजन की आपूर्ति करेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सभी 240 इंजनों की आपूर्ति अगले आठ वर्षों में पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा- 'आपूर्ति कार्यक्रम के अंत तक एचएएल स्वदेशीकरण सामग्री को 63 प्रतिशत तक बढ़ा देगा, जिससे इसका औसत 54 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा।

लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की संख्या घटकर हुई 30

इससे एयरो इंजन के मरम्मत कार्यों में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।' इंजनों के लिए यह सौदा वायुसेना के लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन में कमी आने और एचएएल द्वारा तेजस विमान की आपूर्ति में देरी संबंधी चिंताओं के बीच हुआ है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की संख्या घटकर लगभग 30 रह गई है जबकि इनकी आधिकारिक स्वीकृत संख्या कम से कम 42 है।

रिश्तों के रंग बहुत गहरे होते हैं : विजय गर्ग

वह समाज में सोचने, बात करने, चलने, उठने-बैठने के अलग-अलग तरीके अपनाने लगता है। उसके दिल और दिमाग में जुड़ाव, रिश्ते, प्यार, भावनाओं के रंग पारिवारिक रिश्तों जितने घनिष्ठ नहीं होते। उसे प्रायः औपचारिक जीवन जीना पड़ता है। वह अपने से अधिक पद, धन, प्रसिद्धि वाले व्यक्ति से नीच रहकर तथा मधुर स्वर में नम्रतापूर्वक बात करके मिलता है। आदिकाल से ही मनुष्य ऐसा जीवन जीने का आदी रहा है जो अपने रिश्तों की गर्माहट को संजोता है। समय के साथ-साथवह प्रगति करते हुए परिवार से लेकर समाज, गांव, देश, देश तक अपने रिश्तों को बनाने और बनाए रखने का प्रयास करता है। सोचने, बोलने, समझने, पढ़ने, आज्ञा मानने जैसे सूक्ष्म गुणों के कारण वह समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार अपने परिवार और आसपास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और संवेदनाओं को अपनी निकटता के अनुसार व्यक्त करता रहता है। जन्म के बाद व्यक्ति को सबसे पहली चीज़ अपने परिवार के रक्त संबंधों की गर्माहट का आनंद मिलता है। वह अपने बचपन और बड़े होने के दौरान रिश्तों का जीवन जीता है। उसका मालिक बनोउसे रिश्ते के अनुसार अपने माता-पिता, दादा-दादी, भाई, चाचा-चाची, मामा-मामी से बेहद प्यार मिलता है। इन रिश्तों के रंग बहुत गहरे और शाश्वत होते हैं। स्व-निर्मित या सामाजिक रूप से निर्मित रिश्तों में, पत्नी और सच्चे दोस्तों के बीच का रिश्ता एक आध्यात्मिक आशीर्वाद की तरह होता है। उनके करीबी रिश्तेदारों, रिश्तेदारों, परिवारों, पड़ोसियों, ग्रामीणों, साथियों, स्कूल और कॉलेज के दोस्तों के लिए, चाहे वह बाद में किसी भी बड़े स्थान पर पहुंच जाए, उनकी निकटता पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट की तरह है।अवशेष रिश्तों का जीवन जीते हुए व्यक्ति अपना अधिक से अधिक समय घर पर या अपने रिश्तेदारों के साथ बिताता है, शादियों, जन्मदिनों, मेलों और अन्य पारिवारिक उत्सवों के रंगों और खुशियों का आनंद लेता है, दिल की गहराइयों से उनका आनंद लेता है और वे बने रहते हैं। उनकी यादों में वे पूरी जिंदगी बस जाते हैं। यहां तक कि अपने साथ हुए दुर्भाग्य, घटनाओं और अन्य पीड़ाओं और कष्टों को सहते हुए भी वह बहुत प्रभावित होता है। खुशी के मौकों पर वह खुलकर जश्न मनाते हैं, हंसते हैं और नाचते हैं। दुःख, दुःख, वियोग के समय ही उनकी मृत्यु हुईजे के रोता है. ऐसी खुशियों और दर्द की यादें उसके मन की कृतियों पर कभी न भूलने वाली कहानियों के रूप में अंकित हैं। उसे अपने रिश्ते के महत्व के अनुसार प्यार और सम्मान मिलता है और रिश्तों के महत्व के अनुसार छोटे-बड़े और अन्य रिश्तों की गरिमा का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। इसके बाद जब मनुष्य संसार में घूम-घूमकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, चाहे वह कोई पितृसत्तात्मक कार्य करता हो, चाहे कोई नया व्यापार या व्यवसाय प्रारम्भ करता हो, चाहे वह कोई भी बड़ा अध्ययन-लेखन करता हो।जब वह छोटे पद पर काम करने लगता है तो हैसियत के अनुसार जीवन जीने लगता है वह समाज में सोचने, बात करने, चलने, उठने-

बैठने के अलग-अलग तरीके अपनाने लगता है। उसके दिल और दिमाग में जुड़ाव, रिश्ते, प्यार, भावनाओं के रंग पारिवारिक रिश्तों जितने घनिष्ठ नहीं होते। उसे प्रायः औपचारिक जीवन जीना पड़ता है। वह अपने से अधिक पद, धन, प्रसिद्धि वाले व्यक्ति से नीच रहकर तथा मधुर स्वर में नम्रतापूर्वक बात करके मिलता है। अपने से छोटे को, अपने से बुरे को, अपने मातहतों को अपने से छोटे कर्मचारियों कोवह आदेशात्मक लहजे में बोलता है। किसी के सुख से दुःख की ओर जाना भी एक संस्कार बन जाता है। न तो किसी की खुशियों के रंग उतने गहरे और दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, न ही किसी के दुख, दर्द और तकलीफें लंबे समय तक यादों का हिस्सा बन पाती हैं। इस प्रकार मनुष्य संसार में भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार से रिश्तों और स्थितियों का जीवन जीता और उसका आनंद लेता है। संबंध जीवन की यादों के रंग सुंदर, अंतरंग, स्थायी और आनंददायक होते हैं जबकि स्थिति जीवन के रंग औपचारिक, व्यावसायिक और होते हैंव्यावहारिक हैं.

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023